0k"kZ % 40(vad % 04 (vizy % 2018(eY; % nl #Ik,

सीटू मजदूर

सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस

जनरल कौंसिल बैठक

23—26 मार्च 2018, कोझिकोड़, केरल

मार्च का नेतृत्व करते हुए

केरल के मुख्यमंत्री पिन्नरायी विजयन कालीकट में समुद्र तट पर मजदूरों की विशाल रैली को संबोधित करते हुए

सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस

जनरल कौंसिल बैठक

23–26 मार्च 2018, कोझिकोड़, केरल

महासचिव तपन सेन रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए;

(दायें) **स्वागत समिति के चेयरमैन ई. करीम द्वारा जनरल कौंसिल सदस्यों का स्वागत;**

(बायें) **के. हेमलता अध्यक्षीय संबोधन करते हुए**

केरल में 2 अप्रैल की ऐतिहासिक हड़ताल

(रिपोर्ट पृ० 16)

सीटू मजदूर

lhvkbVh;w dk e[ki=

अप्रैल 2018

सम्पादक मण्डल

सम्पादक

के हेमलता

कार्यकारी सम्पादक

जे एस मजुमदार

सदस्य

तपन सेन,
एम एल मलकोटिया,
कश्मीर सिंह ठाकुर,
पुष्पेन्द्र त्यागी,
एच.एस.राजपूत

अंदर के पृष्ठों पर

सीटू जनरल कौंसिल की बैठक 5

केरलमें 2 अप्रैल की हड़ताल –इलामारम करीम 16

किसानों का ऐतिहासिक लाँग मार्च 17

उद्योग व क्षेत्र 23

राज्यों से 24

अंतर्राष्ट्रीय 25

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 26

सम्पादकीय

बढ़ता प्रतिरोध

gky e dkf>dkM e lEiUu g;h lhV dh tujy d,mfly u vkfFkd ,o lkekftd :i l fiNM rcdk e mHkj çfrjk/k dk j[kkfdr fd;k g A ftldh rhork gky d nkj e mYy[kuh; rth l c<h g A uoEcj e fnYyh e etnjk dk egkiMko] 60 yk[k Ldhe odll dh 17 tuojh dh n'k0;kih gMrky] ftle n'k d 60 çfr'kr ftyk e 20 yk[k Ldhe odll lMdk ij fudy A jktLFkku d fdlkuk d fojkV vknkyu d ckn egkjk"V d fdlkuk dh llrkg Hkj dh in;k=k vkj vHkh vHkh ,l lh@,l Vh ,DV dk detkj dju dh dkf'k'kk d fo#) n'k Hkj e meMk tcjnLr fojk/k vkj ml ij ifyl rFkk tkfroknh fxjkgk d xkyhpkyu e 10 ykxk dh ekr& ftue lcl vf/kd l[;k e/;çn'k l gA bu lcl lkQ g fd n'k d ofpr vkj 'kkf"kr rcd edkcy e [kM gk jg g A

vku oky fnuk e 0;kid l;ä vknkyuk dk flyflyk 'k: gku tk jgk gA 23 eb dk tu ,drk&tu vf/kdkj vknkyu d rgr uomnkjokn] lkEçnkf;drk vkj tkfr mRihMu d fo#) n'k0;kih fojk/k dk;okfg;k dh tk;xhA bld ckn lR;kxg vknkyu gkxk ftle vf[ky Hkkjrh; fdlku lHkk d urRo e fxj¶rkfj;k nh tk;xh] lhV dh vxvkb e etnj ox Hkh ble 'kkfey gkxk A 5 flrEcj dk lhV dh vxvkb e 2 yk[k Jfedk dh jyh fnYyh e gkxh] ftle fdlku lHkk rFkk [kretnj ;fu;u dh vxvkb e fdlku rFkk xkeh.k lo gkjk Hkkx yxk ; vyx&vyx lDVjk o m|kxk e lk> ,oe Lor= vkUnkyu] db db fnuk dh gMrky Hkh dh tk;xh] ftudk dk;Øe VM ;fu;l cuk,xh A

bl rjg d oxh; vkj lkekftd vkUnkyuk e bl tíktgn dk jktuhfrd Åpkb rd igpku dh lkeFk; g A ;g og le; g tc lhV dk viuk lkxBfud l–<hdj.k djuk gkxk] i[rk ldYi vkj Qkyknh bPNk 'kfä d lkFk dMk ifjJe djuk gkxk A lhV dk vo'; viuh ,frgkfld ftEenkjh ijh djuh gkxh A

शोक संवेदना

कॉमरेड रमाकान्त पांडे

उर्वरक (फर्टिलाइजर) मजदूरों के अनुभवी राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन नेता व फर्टिलाइजर वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एफ डब्लू एफ आइ) के अध्यक्ष कॉमरेड रमाकांत पांडे का 14 मार्च को गोरखपुर में अपने आवास पर निधन हो गया। वे 81 वर्ष के थे। वे, 1974 में एफ डब्लू एफ आई की स्थापना से ही उसके अध्यक्ष थे।

कॉमरेड पांडे ने युवा ट्रेड यूनियन नेताओं की एक टीम के साथ पूर्ववर्ती फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया की विभिन्न इकाईयों में, फर्टिलाइर सैक्टर में सीटू, एटक, एच एम एस से संबद्ध व स्वतन्त्र 32 यूनियनों को सफलतापूर्वक साथ लाकर एफ डब्लू एफ आई की स्थापना की थी। उन्होंने फर्टिलाईजर मजदूरों के मुद्दों को लेकर व सार्वजनिक क्षेत्र की उर्वरक इकाईयों को बंद करने के केन्द्रीय सरकारों के फैसलों के खिलाफ हड़ताल समेत कितने ही जुझारू संधर्षो का नेतृत्व किया था। सीटू, दिवंगत नेता कॉमरेड रमाकांत पांडे को अपनी आदरपूर्ण श्रद्धांजलि भेंट करता है और उनके परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक शोक संवेदना प्रकट करता है।

सीटू ने दलितों के शांतिपूर्ण विरोध पर अत्याचारों व पुलिस गोलीबारी की निंदा की

3 अप्रैल को जारी एक बयान में सीटू ने, 2 अप्रैल के दलितों के शांतिपूर्ण विरोध पर अत्याचारों व पूलिस गोलीबारी की निंदा की।

सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में दिये गये एक फैसले में एस सी/एस टी एक्ट को कमजोर किये जाने के विरोध में विभिन्न दलित संगठनों ने 2 अप्रैल, 2018 को भारत बंद का आहवान किया था जिसे देश भर में अच्छा–खासा समर्थन मिला। सीटू ने भी केन्द्र सरकार से संसद द्वारा पारित अधिनियम को इस प्रकार से कमजोर किये जाने को रोकने के लिए समीक्षा याचिका दायर करने और उचित विधायी कार्रवाई किये जाने की माँग की थी।

भाजपा सरकार ने, 4 वर्षों के अपने कार्यकाल में सरकारी प्रशासन के संरक्षण व मिली भगत के साथ अपने विभिन्न संगठनों के द्वारा समूचे देश में दलितों के खिलाफ जारी संगठित अत्याचारों का एक कुख्यात रिकार्ड बनाया है। इसने, 2 अप्रैल को देश के विभिन्न हिस्सों में दलित संगठनों द्वारा आयोजित विरोध कार्रवाईयों पर बर्बर हमले किये जिनमें मध्यप्रदेश के ग्वालियर, भिंड, मुरैना में 6 लोगों की और राजस्थान के अलवर में एक व्यक्ति की तथा यू पी में दो लोगों की मौत हो गई, ये सभी राज्य भाजपा शासित हैं। देश में कई और स्थानों पर भी दलितों व आम जनता के विरोध कार्यक्रमों पर पुलिस ने ऐसे ही हमले किये।

सीटू ने भाजपानीत सरकारों द्वारा दलितों की हत्याओं व उन पर ढाये गये अत्याचारों की भर्त्सना की ओर ऐसे बर्बर हमलों व हत्याओं के विरोध में मजदूरों से एकजुट आवाज बुलंद करने का आहवान किया। सीटू, न्याय के लिए व अत्याचारों से बचाव के लिए दलितों के संधर्षों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए सरकार से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तुरन्त समीक्षा के लिए मजबूत हस्तक्षेप करने तथा एस सी/एस टी अत्याचार निवारक अधिनियम को कमजोर किये जाने से बचाने के लिए समुचित विधायी कदम उठाये जाने की अपनी माँग को दोहराता है।

सीटू जनरल कौंसिल की बैठक

दिशा में स्पष्ट व कार्रवाई में दृढ़

सीटू की 425 सदस्यीय राष्ट्रीय जनरल कौंसिल की 4 दिवसीय बैठक 23–26 मार्च, 2018 तक केरल के कोझिकोड़ में कॉमरेड मोहम्मद अमीन नगर (टाऊन हाल) में हुई जिसमें 53 महिलाओं सहित 375 सदस्यों; व स्वतंत्र राष्ट्रीय फेडरेशनों के 14 व राज्यों से 12 विशेष आमंत्रितों ने भाग लिया। जनरल कौंसिल ने भाजपा व आइ पी एफ टी के गुंडों के खिलाफ लड़ रहे त्रिपुरा के लोगों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने का प्रस्ताव पारित किया।

जनरल कौंसिल बैठक को संबोधित करते हुए स्वागत समिति के चेयरमैन, सीटू के राष्ट्रीय सचिव व उसके राज्य महासचिव इलामारम करीम ने, संविधान की सीमाओं के दायरे में केरल की वाम नेतृत्व वाली एल डी एफ सरकार द्वारा लागू किये जा रहे विकास के वैकल्पिक रास्ते के बारे में बताया जिसमें (i) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पुनवर्जीवित करना व उन्हें मजबूत करना; (ii) परम्परागत क्षेत्रों को बढ़ावा देना व उन्हें फिर से मजबूती प्रदान करना; (iii) विभिन्न सैक्टरों में न्यूनतम वेतन का बढ़ाया जाना; (iv) केन्द्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों व कानूनों को राज्य में हुए लागू करने से इनकार करना आदि शामिल हैं। केरल के समूचे मजदूर वर्ग व जनता के अन्य सभी तबकों ने स्थायी रोजगारों को 'तय अवधि के रोजगार' से बदलने की केन्द्र सरकार की अधिसूचना को वापस लिये जाने की माँग करते हुए, 2 अप्रैल को समूचे राज्य में बंद में स्वस्फूर्त भागेदारी कर इस वैकल्पिक रास्ते के लिए अपने मजबूत समर्थन का इजहार किया। जनरल कौंसिल बैठक ने केरल में हड़ताल के समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया तथा 2 अप्रैल को ही देश भर में विरोध कार्रवाईयाँ आयोजित किये जाने का आहवान किया। केरल के मुख्यमंत्री पिन्नरायी विजयन ने जनरल कौंसिल बैठक के समापन के लिए आयोजित मजदूरों की रैली व जनसभा को संबोधित करते हुए, भाजपानीत केन्द्र सरकार द्वारा तय अवधि के रोजगार की अधिसूचना से मजदूरों व ट्रेड यूनियन आंदोलन को पैदा खतरे के बारे में बताने से अपनी बात शुरू की तथा केरल में 2 अप्रैल की हड़ताल का पूरा समर्थन करते हुए इस अधिसूचना के खिलाफ समूचे देश में आंदोलन का समर्थन करते हुए केरल में जनता के विकास के वैकल्पिक रास्ते के बारे में बताया।

के. हेमलता ने अपने अध्यक्षीय भाषण में, विकास के प्रमुख पहलुओं तथा वैश्वीकरण की नीतियों के खिलाफ दुनिया भर में मजदूर वर्ग के विभिन्न तबकों के उभरते संघर्षों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम मजदूर वर्ग व जनता के सामने विकल्प पेश करें तथा ऐसे विकल्प के लिए लड़ने के लिए उन्हें लामबंद करें।

जनरल कौंसिल की बैठक दो अलग–अलग सत्रों में हुई। पहले सत्र में, तपन सेन ने महासचिव की रिपोर्ट पेश की तथा संविधान में संशोधन प्रस्तावित किये; तथा हेमलता ने कार्यक्रमों व कार्यों के बारे में एक पॉवर पॉईन्ट प्रस्तुति दी। इन सभी तीन दस्तावेजों पर बहस में 49 सदस्यों ने हिस्सा लिया। दूसरे सत्र में, महासचिव ने संगठन पर सीटू के अद्यतन दस्तावेज का मसविदा प्रस्तुत किया जिसे आमतौर पर भुवनेश्वर दस्तावेज के नाम से जाना जाता है। इस मसविदे पर चर्चा में 37 सदस्यों ने भाग लिया। उन्होंने चर्चा की दिशा व विषयवस्तु के बारे में सामने आयी सर्वसम्मति का जिक्र किया।

चर्चा का सार–संक्षेप

महासचिव की रिपोर्ट : महासचिव की रिपोर्ट पर चर्चा 8 बिन्दुओं पा केन्द्रित थी– (i) जी एस टी का प्रभाव; (ii) एन सी एल टी को बी आइ एफ आर; (iii) संविधान की सीमाओं में वाम नेतृत्व की सरकार द्वारा वैकल्पिक नीतियों का लागू किया जाना; (iv) नवउदारवादी नीतियों के खिलाफ देश भर में वैकल्पिक नीतियों को तथा उनके पीछे की वर्गीय राजनीति को सामने रखे जाने की जरूरत; (v) लोगों के जीवन व जीविका पर हो रहे हमले पूंजीवाद की नवउदारवादी नीतियों का परिलक्षण है; (vi) मजदूरों– किसानों की बढ़ती एकता व संयुक्त संघर्ष; (vii) नवउदारवादी नीतियों व साम्प्रदायिकता के खिलाफ संयुक्त वर्गीय व जन आंदोलन तथा जे ई जे ए ए का गठन; तथा (viii) स्वतंत्र व संयुक्त ट्रेड यूनियन आंदोलन का निर्माण।

अद्यतन संगठन दस्तावेज : संगठन पर अद्यतन दस्तावेज पर चर्चा जनवादीकरण की मूल भावना; व्यक्तिगत जिम्मेदारी के साथ सामूहिक प्रयासों; प्रोद्योगिकी व संपत्ति संबंध; बेरोजगारी का मुद्दा व युवाओं को शामिल कर आंदोलन के निमार्ण; सदस्यता के दायरे के आगे तक असर डालने वाली कार्रवाईयों से पैदा प्रभाव को संगठन की मजबूती में बदलना; अभियान के नवाचारी तरीके; नई कार्य संस्कृति; अभियान के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग; फेडरेशनों व राज्यों के बीच संसक्ति को मजबूत बनाने; लोगों के मुद्दों व देश की संप्रभुता के हितों से जुड़े हुए रेल व रक्षा क्षेत्र के निजीकरण की ओर ध्यान केन्द्रिंत करना; हिन्दी भाषी राज्यों पर विशेष ध्यान; राज्यों में पूर्ण सचिवमंडल द्वारा मध्यावधि समीक्षा; नेताओं के एक से ज्यादा यूनियनों में होने पर रोक, प्रतिष्ठान यूनियनों के प्रमुख पदों पर सेवारत व्यक्तियों का होना; ऑल इंडिया फेडरेशनों में सेवारत व्यक्ति, गैर–सेवारत व्यक्ति आवश्यकतानुरूप

संविधान पर : (i) सीटू द्वारा यूनियनों के सदस्यों से जमा किये जाने वाले संबंधता शुल्क 2018 में जिसे 2019 में संबंधता शुल्क के रूप में दिया जाना है को 1 रूपये से बढ़ाकर 2 रूपये प्रति सदस्य/प्रतिवर्ष किया गया है; (ii) यूनियन का न्यूनतम सदस्यता सब्सक्रिप्शन 12 रूपये रहेगा; (iii) जिला व नीचे के स्तर की समितियाँ सीटू की अंतर समितियां नहीं हैं बल्कि वे यूनियनों व उनकी इकाईयों की समन्वयकारी निकाय हैं।

निष्कर्ष : पारित कार्यक्रमों व कार्यों के साथ विस्तार व हस्तक्षेप के मौके के साथ सीटू की जिम्मेदारी बढ़ जाती है।

जनरल कौंसिल बैठक ने प्रस्ताव भी पारित किये–अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारक) अधिनियम को कमजोर करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गंभीर चिन्ता व्यक्त करते हुए; जे एन यू के आंदोलनकारी छात्रों व शिक्षकों पर पुलिस अत्याचारों की निंदा करते हुए; 26–28 मार्च, 2018 की क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तीन दिन की हड़ताल का समर्थन व एकजुटता व्यक्त करते हुए; रोहिंग्या के विरूद्ध राज्य प्रायोजित आतंकवाद की निंदा करते हुए तथा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की देख–रेख में उनकी सुरक्षित वापसी व पुनर्वास के लिए भारत सरकार से कदम उठाने की माँग करते हुए; आई टी व आई टी ई एस कर्मचारियों को संगठित करने के लिए; तथा ई पी एफ के तहत पेंशन धारकों के मुद्दों पर।

अपने समापन भाषण में अध्यक्ष हेमलता ने सीटू को राजनीतिक, वैचारिक व सांगठनिक रूप से विकसित करने पर जोर दिया। जनरल कौंसिल स्तर की कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति की रिपोर्ट का संदर्भ देते हुए, जो जी सी एम से एक दिन पहले हुई थी, उन्होंने पंजाब, हरियाणा, आंध्रप्रदेश व तेलंगाना में सीटू कार्येर्ताओं पर सत्ता धारियों के हमलों के बारे में बताया। संगठन की मजबूती के लिए उन्होंने संगठित क्षेत्र के प्राथमिकता के क्षेत्रों– बिजली, परिवहन व निजी क्षेत्रों के उद्योगों का; योजना कर्मियों के महत्व का तथा देश के 60 प्रतिशत जिलों में संगठनात्मक रूप से फैलने का जिक्र किया कि वे राजनीतिक व वैचारिक रूप से अहम भूमिका अदा कर सकती हैं। उन्होंने राज्यों से कैडर को शामिल कर, जिनमें से कुछ जल्द ही शामिल हो रहे हैं, सीटू केन्द्र की मजबूती पर जोर दिया। उन्होंने राजनीतिक व वैचारिक रूप से विकसित होने की जरूरत व जल्द ही शुरू होने वाले पी आर भवन की इसमें भूमिका की व उचित योजना तथा पाठृयक्रम की तैयारी की चर्चा की। उन्होंने योजना व कैडर के विकास पर जोर दिया।

स्वागत समिति के जनरल कन्वीनर ए.के.रमेश ने जनरल कौंसिल सदस्यों को धन्यवाद देते हुए 18 सेमिनारों, प्रगतिशील नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जी सी एम की तैयारियों के लिए जिले के मजदूरों व जनता को शामिल करने तथा बैठक को सफल व यादगार बनाने के लिए सदस्यों द्वारा घर–घर जाकर चंदा जमा करने के बारे में बताया।

जन सभा

जनरल कौंसिल बैठक के लिए स्वागत समिति व सीटू की जिला समिति द्वारा दो महीने लम्बी तैयारियों में न केवल मजदूर व उनके परिवारों के सदस्य शामिल थे बल्कि, यूनियनों की बैठकों, अलग–अलग मुद्दों पर आयोजित जिला स्तरीय सेमिनारों, जन सभाओं, जत्थों आदि के माध्यम से आम लोगों को भी शामिल किया गया था जो 26 मार्च को कालीकट के समुद्री किनारे पर एक लाख से ज्यादा की रैली में दिखाई पड़ रहा था। मजदूरों की लामबंदी जो केवल जिले से ही थी, झंडो, झंडियों के साथ छोटी–छोटी रैलियों के द्वारा समुद्र किनारे पर हुई थी, जिसमें महिलाओं की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी थी।

जन सभा की अध्यक्षता केरल की एल डी एफ सरकार के श्रम मंत्री टी पी रामकृष्णनन ने की। केरल के मुख्यमंत्री पिन्नरायी विजयन ने, जो सभा के मुख्य वक्ता थे, तय अवधि के रोजगार के बारे में केन्द्र सरकार के फैसले के विरोध में 2 अप्रैल को हड़ताल करने के केरल के मजदूर वर्ग के फैसले पर उन्हें बधाई देने से अपना भाषण शुरू किया था। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार किस प्रकार मजदूर–विरोधी व जन–विरोधी नीतियों को आगे बढ़ा रही है तथा जनता का प्रत्येक तबका, विशेषकर मजदूर व किसान इन

नीतियों व इनके प्रभावों का प्रतिरोध कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से एल डी एफ सरकार अपनी सीमाओं के भीतर कुछ जन–हितैषी वैकल्पिक कदमों को लागू करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने कैसे बहुत ही कम समय में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों को पुनवर्जीवित और सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं को मजबूत किया है। उन्होंने, केरल के विकास में प्रवासी मजदूरों के योगदान को सरकार द्वारा मान्यता दिये जाने का और एल डी एफ की केरल सरकार द्वारा अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा के लिए उठाये गये नये कदमों व कानूनी उपायों का जिक्र किया।

तपन सेन, के.हेमलता, ए.के.पद्मनाभन, सीटू की केरल राज्य समिति के अध्यक्ष अनन्थलावत्तम आनंदन ने भी जनसभा को संबोधित किया। इलामारम करीम ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

(जनरल कौंसिल द्वारा पारित)

कार्यक्रमों की प्रमुख बातें

अप्रैल–अगस्त, 2018

सीटू का स्वतंत्र अभियान

23 मई, 2018

जे ई जे ए ए के जिला स्तरीय व निचले स्तर के प्रदर्शनों में शामिल होना

– मजदूरों के बीच सप्ताह भर का तैयारी अभियान

30 मई, 2018

सीटू स्थापना दिवस : अखिल भारतीय शपथ दिवस

–मजदूर, सीटू केन्द्र द्वारा तैयार शपथ धोषणा की शपथ लेंगे

9 अगस्त, 2018

भारत छोड़ो दिवस : जिलों में गिरफ्तारी देने के कार्यक्रम

–मजदूरों की अलग माँगों के साथ

14–15 अगस्त, 2018 रात्रि

स्वतन्त्रता दिवस : रात भर का ''सामूहिक जागरण''

स्वतन्त्रता संग्राम की भविष्य दृष्टि को आत्मसात करने व उसका प्रचार–प्रसार करने के लिए

5 सितम्बर, 2018

सीटू का दिल्ली चलो : ए आइ के एस व ए आइ ए डब्ल्यू यू शामिल होंगे

– देश भर से कम से कम 2 लाख मजदूरों की लामबंदी

अक्टूबर–नवम्बर 2018

संयुक्त ट्रेड यूनियन कार्यकम

– सैक्टरवार व आम मजदूरों की बहुदिवसीय हड़ताल की तैयारी, जैसा केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों व फेडरेशनों द्वारा तय होगा

2020 में

सीटू की 1 करोड़ सदस्यता

– तुरन्त ही चहुमुखे सदस्यता अभियान के आहवान के लिए

कार्य व समय सीमा

(जनरल कौंसिल बैठक द्वारा पारित)

1. 5 सितम्बर की दिल्ली लामबंदी की तैयारियां

अप्रैल–मई–अखिल भारतीय व राज्य केन्दों पर; जून में जिलों पर; जुलाई–निचले स्तर पर; अगस्त– अखिल भारतीय व क्षेत्रीय जत्थे

2. संगठन पर अद्यतन दस्तावेज को प्रभावी ढंग से लागू करो

3. ऑल इंडिया सेंटर

7 अप्रैल तक संगठनात्मक दस्तावेज को अंतिम रूप देकर अद्यतन दस्तावेज को भेजना तथा 'रिपोर्टिंग के बिन्दु भेजना'; विभिन्न मुद्दों पर 'जन हितैषी विकल्प' का मसाविदा तैयार करना; प्रचार–अभियान सामग्री–पुस्तिकाओं, बातचीत के बिन्दु, नारे आदि का मसविदा तैयार करना; मददगारों की सूची तैयार करना; देख–रेख/निगरानी के लिए टीम गठित करना;

4. राज्य समितियाँ

'संगठन पर अद्यतन दस्तावेज' को 15 अप्रैल तक स्थानीय भाषाओं में अनुदित करो तथा उसे राज्य समितियों राज्य स्तर की यूनियन समितियों–ऑल इंडिया फेडरेशनों की राज्य समितियों–सीटू जिला कमेटियों–जिला स्तरीय यूनियन समितियों सबसे निचले स्तर की समितियों के संयोजकों तथा सीटू की सभी संबद्ध यूनियनों के अध्यक्ष व सचिवों तक पहुँचाओ;

सबसे निचले स्तर की समितियों के सभी सदस्यों तक पहुँचने के लिए रिपोर्टिंग के बिन्दुओं का अनुवाद कर उन्हें जरूरी संख्या में छपवाओं;

'संगठन पर अद्यतन दस्तावेज' के बारे में समुचित तैयारियों के साथ राज्य स्तरीय कार्यशालायें आयोजित करो, कोशिश हो कि दो दिन की हों, मजबूती व विस्तार पर केन्द्रित संगठन पर राज्य का दस्तावेज तैयार करो; जिन्होंने पहले से तैयार किया हुआ है– वे आवश्यकतानुसार उसकी समीक्षा/अद्यतन करें; संगठन की मौजूदा स्थिति के ठोस आकलन तथा विस्तार के अवसरों के उपयोग की योजना पर दस्तावेज का मसविदा तैयार करो; स्वतंत्र अभियान व लामबंदी के लिए विस्तृत योजना तैयार करो;

5. संगठन पर राज्य कार्यशाला

जनवादी कार्यप्रणाली– विस्तार व प्राथमिकता–कैडरों के राजनीतिक व वैचारिक विकास–अखिल भारतीय स्तर पर पारित कार्यो की तर्ज पर राज्य में भविष्य के संगठनात्मक कार्य तैयार करो; कामकाजी महिलाओं के बीच कार्य के बारे में सीटू के दृष्टिकोण पर चर्चा करो; राज्य में कामकाजी महिलाओं के बीच कार्य की योजना बनाओ;

6. स्वतंत्र अभियान के बारे में राज्य कार्यशाला

जिला व निचले स्तर की कमेटियों की बैठकों के लिए समय अन्तराल तय करो; अखिल भारतीय केन्द्र से प्राप्त सामग्री के अनुवाद की योजना बनाओ; राज्य स्तरीय अभियान सामग्री तैयार करने की योजना बनाओ

अभियान का तरीका तय करो; जिन तक नहीं पहुँचे हैं उन तक पहुँचने के लिए सदस्यता के दायरे के बाहर मजदूरों तक पहुँचने का सैक्टर वार लक्ष्य निर्धारित करो;

7. राज्य कार्यशालायें

राज्य के प्रभारी अखिल भारतीय पदाधिकारी भाग लें और दिशा–निर्देश करें; राज्य वर्कशॉप के फैसलों के अनुरूप राज्य पदाधिकारियों को राज्य व सैक्टर की जिम्मेदारी दो; राज्य केन्द्र व पदाधिकारी क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा व देख–रेख करे; उत्तरदायित्व तय करो;

8. गतिविधियों की विस्तृत मात्रात्मक जानकारी रखो :

परचों, पुस्तिकाओं, पोस्टरों आदि का प्रकाशन (जिलेवार व सैक्टरवार); अलग–अलग सभाओं व जत्थें के द्वारा जितने मजदूरों तक पहुँचा गया; दिल्ली में कितने मजदूरों की लामबंदी की गई;

समय सीमा

राज्यों के लिए जून में : यूनियनों की जनवादी कार्यप्रणाली, मजबूती व विस्तार को केन्द्र में रख संगठन पर अद्यतन दस्तावेज की रिपोटिंग; यूनियनवार मजदूरों तक पहुँचने व उन्हें लामबंद करने के ठोस लक्ष्य के साथ जिलों में स्वतंत्र अभियान की विस्तृत योजना;

राज्यों के लिए जुलाई में

सबसे निचले स्तर पर अभियान– गेट मीटिंगें, समूह बैठकें, परिवार मिलन, रिहायशी इलाकों की बैठकें; बातचीत के बिन्दुओं पर चर्चा– सांस्कृतिक रूप, परचे, पुस्तिकायें, बैनर, पोस्टर आदि; योजना कर्मियों, निमार्ण मजदूरों, पंचायत मजदूरों आदि के माध्यम से सुदूर गांवों तक पहुँचों;

अगस्त में ऑल इंडिया व क्षेत्रीय जत्थे : जत्थों का नेतृत्व केन्द्रीय नेताओं/अखिल भरतीय पदाधिकारियों द्वारा; राज्य के नेता शामिल रहेंगे; सभी प्रमुख जिला मुख्यालयों तथा प्रमुख औद्योगिक संक्रलो/इलाकों तक जाने के लिए राज्य में उप–जत्थें की योजना तैयार करो; जहाँ–जहाँ संभव हो सभी उपखंडों तक पहुँचने के लिए जिला उप जत्थों की योजना बने।

उद्देश्य

- मेहनतकश जनता के सभी तबकों में जोश पैदा करने के लिए;
- चेतना का स्तर बढ़ाने के लिए;
- दिल्ली में अधिकतम लामबंदी करने के लिए जो 2 लाख से कम न हो;

हमारे लिए अहम परीक्षा

- ➢ संगठन पर अद्यतन दस्तावेज पर अमल करना;
- ➢ राजनीतिक व वैचारिक रूप से चेतना संपन्न कैडर विकसित करना;
- ➢ भाजपानीत सरकार की नवउदारवादी व सांप्रदायिक नीतियों को बदलने के लिए राजनीतिक बदलाव का माहौल तैयार करना;

संकल्प

- ✓ हम निश्चित ही सफल होंगे;
- ✓ हम सीटू को उसकी संविधानिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए राजनीतिक व वैचारिक रूप से लैस एक अखिल भारतीय जुझारू व ताकतवर संगठन के रूप में विकसित करेंगे।

जनरल कौंसिल बैठक के प्रस्ताव

त्रिपुरा की जनता के साथ एकजुटता में खड़े हो; जनतन्त्र व एकता की रक्षा करो

केरल के कोझिकोड़ में 23 से 26 मार्च, 2018 तक हो रही सीटू की जनरल कौंसिल की यह बैठक, त्रिपुरा में सत्ता में आने के तुरन्त बाद वहाँ भाजपा/आर एस एस के गुण्डों द्वारा त्रिपुरा की जनता विशेषकर वाम दलो व वाम रूझान वाले जन संगठनों के समर्थकों को निशाना बनाकर किये जा रहे बर्बर हमलों पर गंभीर चिन्ता व्यक्त करती है।

भाजपा व उसकी सहयोगी आइ पी एफ टी के हमले मतगणना के दिन भाजपा की जीत स्पष्ट होने के साथ ही शुरू हो गये थे। तब से लेकर वाम दलों के सदस्यों, कैडरों व समर्थकों पर शारीरिक हमले व उनके घरों को जलाना, संपत्तियों की लूट व उसे तहस–नहस करना, वाम दलों व सीटू समेत कई जनसंगठनों के दफ्तरों पर कब्जे व उन्हें जलाने का सिलसिला राज्य भर में जारी है। राज्य प्रशासन मूक दर्शक बना रहा है। इन हमलों में सैंकड़ों वाम कैडर व कार्यकर्ता घायल हुए हैं और बहुतों को अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा है। सीटू के दफ्तर, विशेषकर त्रिपुरा मोटर श्रमिक यूनियन के दफ्तरो को भाजपा गुंडो ने हमलों का निशाना बनाया है। इनमें से बहुत से दफ्तरों पर ताले लगा दिये गये हैं; सीटू के झंडे उतार कर भाजपा के झंडे जबरन लगा दिये गये हैं। सहकारी समितियों के बहुत सारे दफ्तरों को भी इसी तरह से आयोजकों व लाभान्वितों को जबरन बाहर कर कब्जा लिया गया है। भाजपा की मातृ संस्था आर एस एस के विचार जहाँ जर्मनी और इटली में हजारों लोगों का कत्ले आम करने वाले हिटलर व मुसोलिनी जैसे फासीवादियों की प्रशंसा करते हैं वहीं उनके समर्थकों ने लेनिन की मूर्ति को गिरा दिया है जिन्होंने रूस में मेहनतकश जनता की मुक्ति के संधर्ष का नेतृत्व किया। देश में इन फासीवादी शक्तियों का पाखंड ऐसा है।

इस हिंसा के करण, कई इलाकों में पुरूष सदस्यों को धर से भाग जाना पड़ा है। भाजपा के गुंडे घर पर बचीं महिलाओं पर भी हमला कर रहे हैं और घर जला डालने व बच्चों को मार डालने की धमकियां देकर भारी मात्रा में पैसा वसूली कर रहे हैं। हजारों कामकाजी लोग बे घर बार के हो गये हैं और आतंक के कारण अपने कार्यस्थलों में जाने में सक्षम नहीं है।

भाजपा शासन के सामने किसी भी तरह के विपक्ष को मौन कर देने के लिए सारे राज्य में आतंक का माहौल पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। यह सुनियोजित हिंसा वामपंथ को विशेषकर ट्रेड यूनियनों व अन्य जनसंगठनों व कल्याणकारी समितियों को समाप्त कर देने के लिए है जो इतने समय तक जनता की भलाई के लिए जनवादी तरीके से काम करती आयी थीं।

सीटू जनरल कौंसिल गर्व के साथ यह नोट करती है कि राज्य सरकार के संरक्षण में बरपा ऐसे आतंक व हिंसा के बावजूद, वामपंथ, ट्रेड यूनियनों व जनवादी आंदोलन के कार्यकर्ता बहादुरी के साथ परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। वामदलों, सीटू व अन्य जन संगठनों के नेता सारे राज्य में प्रभावित लोगों से जाकर मिल रहे हैं और उन्हें सभी आवश्यक मदद व समर्थन प्रदान कर रहे हैं। वे भाजपा नीत राज्य सरकार द्वारा बढ़ावा दिये जा रहे ऐसे संगठित हमलों के खिलाफ लोगों को लामबंद कर आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं।

सीटू जनरल कौंसिल मानती है कि ऐसी बर्बरता व फासीवादी हिंसा आर एस एस व भाजपा की विचारधारा व काम करने के तरीके का हिस्सा है उसमें निहित है। इसका राजनीतिक व सांगठनिक रूप से मुकाबला करना होगा। जनरल कौंसिल त्रिपुरा में मजदूर वर्ग के आंदोलन की शानदार परंपरा व उसके रिकार्ड को याद करती है जिसने पूर्व में कॉंग्रेस शासन के दौरान ऐसी हिंसा व हमलों के खिलाफ शानदार संधर्ष कर उसे सफलतापूर्वक परास्त किया था जब कॉंग्रेस शासन ने अलगाववादी व आंतकी संगठनों से हाथ मिलाया था। राज्य में वाम मोर्चा की सरकार को श्रेय जाता है कि 1993 में पुनः सरकार में आने के बाद उसने राज्य में शांति व भाईचारा स्थापित किया। सीटू जनरल कौंसिल अपना यह पूर्व विश्वास व्यक्त करती है कि इस बार भी त्रिपुरा का मजदूर वर्ग का आंदोलन राजनीतिक, वैचारिक व सांगठनिक रूप से विघटनकारी विध्वंसक व सांप्रदायिक शक्तियों के हमले को परास्त करेगा।

जनरल कौंसिल, भाजपा के हमलों के खिलाफ व त्रिपुरा की जनता के साथ एकजुटता में सीटू राज्य समितियों की पहल पर आयोजित किये गये विरोध प्रदर्शनों को गर्व के साथ नोट करती है। जनरल कौंसिल, संबधताओं से पार जाकर देश भर के मजदूर वर्ग से राज्य में लोकतन्त्र व लोगों की एकता की रक्षा करने के लिए त्रिपुरा के वाम व मजदूर आंदोलन के समर्थन में आगे आने का आहवान करती है।

एस.सी. व एस.टी (अत्याचार निवारक) अधिनियम को कमजोर किये जाने के विरोध में;

केरल के कोझिकोड़ में 23 से 26 मार्च, 2018 तक हो रही सीटू की जनरल कौंसिल बैठक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारक) अधिनियम के प्रावधानों को कमजोर करने वाले उच्चतम न्यायालय के फैसले पर गंभीर चिन्ता व्यक्त करती है।

न्यायाधीशें यू यू ललित व आदर्श गोयल की पीठ द्वारा दिये गये फैसले में जातिगत दमन, उत्पीड़न व दलितों पर रोजमर्रा किये जाने वाले अत्याचारों की सामाजिक वास्तविकता को नजरंदाज किया गया है। इस फैसले ने अग्रिम जमानत पर लगी पाबंदियों को हटाकर और यह शर्त लगाकर कि एक जन सेवक पर उच्च पदस्थ प्राधिकार की मंजूरी के बिना मुकदमा चलाने को लगभग असंभव बना दिया है। निजी कर्मचारियों के मामले में फैसले में कहा गया है कि संबंधित एस एस पी को इसकी मंजूरी देनी होगी।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि केन्द्र सरकार के वकील ने सही प्रतिक्रिया नहीं दी और न ही एक्ट के प्रावधानों को कमजोर करने का विरोध किया। इस फैसले से हुए नुकसान को पलटने के लिए जब तक केन्द्र सरकार उपचारात्मक कदम नहीं उठाती, सामाजिक बराबरी व न्याय की दुश्मन ताकतों के हौंसले दलितों के खिलाफ हिंसा करने के लिए और ज्यादा बुलंद होंगे।

यह जनरल कौंसिल बैठक सरकार से अपील करती है कि वह सुप्रीम कोर्ट की पीठ के प्रतिगामी फैसले के विरोध में अविलम्ब समीक्षा याचिका दाखिल करे।

जे एन यू के आंदोलनरत छात्रों व शिक्षकों पर पुलिस अत्याचार की भर्त्सना करते हुए

केरल के कोझिकोड़ में 23 से 26 मार्च, 2018 तक हो रही सीटू जनरल कौंसिल की यह बैठक नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविधालय के आंदोलनरत छोत्रों व शिक्षकों पर पुलिस अत्याचार की कड़ी भर्त्सना करती है।

बैठक चिंता के साथ नोट करती है कि केन्द्र की भाजपा सरकार के निर्देश पर एक राजनीतिक मकसद के साथ धोर प्रशासनिक कुशासन ने, दशकों से पठन–पाठन के अपने माहौल व स्तर के लिए प्रसिद्ध रहे इस प्रीमियर शिक्षण संस्थान में हालात को बिगाड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ रखी है। प्रशासन की निरंकुश व छदम राष्ट्रवादी कार्रवाईयों से जे एन यू के छात्रों व शिक्षकों दोनों को ही प्रशासन के फैसलों से असहमति व अविश्वास व्यक्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा है और ऐसा करने के लिए उन्होंनें भूख हड़ताल समेत शांतिपूर्ण आंदोलन किया है।

छात्र व शिक्षक अकादमिक स्वतंत्रता के लिए, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने वाली दाखिला नीतियों में बदलाव के विरोध में, जरूरी उपस्थिति के मनमाने फैसले के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रशासन व वाइस चांसलर ने कई छात्रों के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है।

भगत सिंह के शहादत दिवस पर छात्रों व शिक्षकों के प्रतिनिधि निकायों – जे एन यू एस यू व जे एन यू टी ए ने संयुक्त रूप से संसद तक एक पदयात्रा निकालने का आहवान किया था। यह शांतिपूर्ण मार्च यातायात तक को बाधित नहीं कर रहा था। उन्हें मंजिल से बहुत पहले ही पुलिस ने जबरन रोक कर बिना किसी उकसावे के लाठी चार्ज किया। छात्राओं समेत बहुत से छात्रों को गंभीर चोटें आयीं। यहाँ तक कि पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा गया। छात्रों को निशाना बनाकर चलायी गई वॉटर कैनन से जे एन यू के छात्रों व शिक्षकों की रैली के प्रति प्रशासन के बर्बर रवैये का पता चलता है।

पुलिस ने 23 छात्रों को गिरफ्तार भी किया और वह यह बताने के लिए तैयार नहीं थी कि उन्हें कहाँ जे जाया जा रहा था। घायल छात्रों व शिक्षकों को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए छात्रों व शिक्षकों को पुलिस थाने के सामने बैठना पड़ा।

सीटू की यह जनरल कौंसिल बैठक जे एन यू के छात्रों व शिक्षकों पर बिना किसी उकसावे के किए गये इस पुलिस हमले की सख्त भर्त्सना करती है और माँग करती है कि अकादमिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए जे एन यू प्रशासन के सभी निरंकुश फैसलों को वापस लिया जाये तथा यौन उत्पीड़न के आरोप के संबंध में समुचित कार्रवाई की जाये।

रोहिंग्या शरणार्थियों को बचाओ

रोहिंग्या लोगों के खिलाफ बरपा बर्बर व अमानवीय हमले ''जातीय सफाये'' के धृणित कृत्य के बराबर हैं जिसकी तुलना केवल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजी विध्वंस से की जा सकती है। म्यांमार की सरकार अभी तक भी फौज द्वारा किये जा रहे अत्याचारों पर लगाम लगाने में सक्षम नहीं है। म्यांमार से बड़ी संख्या में भाग निकल रहे शरणार्थी और उनके लिए राहत व पुनर्वास के मुद्दे दिन पर दिन गंभीर होते जा रहे हैं।

भारत सरकार ने मामले को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की। रोहिग्याओं के पुरखे भारतीय थे और म्यांमार में उन्हें कोई राजनीतिक व नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं। यहाँ तक कि शादी के लिए भी उन्हें सरकार से पहले इजाजत लेनी पड़ती है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा उनका जिक्र 'सबसे ज्यादा त्रस्त लोगों' में किया गया है।

सीटू की ऑल इंडिया जनरल कौंसिल बैठक जनता के सभी तबकों से रोहिंग्या लोगों के विरूद्ध ''राज्य प्रायेजित आतंकवाद'' की निंदा करने का आहवान करती है और भारत सरकार से, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की निगरानी में उनकी सुरक्षित वापसी व पुनर्वास के लिए कदम उठाने की मांग करती है। सिर्फ उन्हें वापस भेज देना भर तो उन्हें मौत के मुंह में धकेलना होगा। इसलिए यह जनरल कौंसिल रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करती है और माँग करती है कि सरकार झूठे प्रोपेगेंडा से बचे और शरणार्थियों के अधिकारों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के हिसाब से तुरन्त कार्रवाई करे।

नई संबद्धतायें

सीटू की जनरल कौंसिल बैठक ने परिचयपत्र समिति की जाँच पड़ताल के बाद 100 नई यूनियनों को संबद्धता प्रदान की जिनके 44, 395 सदस्य हैं; 8 और यूनियनों को तिनके 1016 सदस्य हैं, जरूरी दस्तावेज जमा करने और केन्द्र से सत्यापित होने तक प्रोविजनल संबद्धता प्रदान की। इनमें अरूणाचल प्रदेश से 18 यूनियने (1723 सदस्य); असम से 1 (163 सदस्य); दिल्ली से 1 (748 सदस्य); हिमाचल प्रदेश से 3 (187 सदस्य); झारखंड से 4 (9480 सदस्य); मध्यप्रदेश से 3 (471 सदस्य); महाराष्ट्र से 6 (788 सदस्य); ओडिशा से 3 (467 सदस्य); पंजाब से 2 (472 सदस्य); राजस्थान से 3 (286 सदस्य); उत्तरप्रदेश से 1 (70 सदस्य); उत्तराखंड से 3 (1000 सदस्य); व पश्चिम बंगाल से 7 (20759 सदस्य) शामिल हैं।

सीटू जनरल कौंसिल बैठक का संदर्भ

के.हेमलता

हेमलता के अध्यक्षीय संबोधन और तपन सेन द्वारा पेश महासचिव की रिपोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय परिस्थिति के संदर्भ में संगठनात्मक व आंदोलनात्मक कार्यों को जनरल कौंसिल के समक्ष रखा।

विकसित पूंजीवादी देशों समेत विश्व के विभिन्न भागों में मजदूर व अन्य मेहनतकश हड़तालों सहित संधर्षों में उतर रहे हैं जो उनकी संबंधित सरकारों द्वारा लागू की जा रहीं नवउदारवादी नीतियों के कारण मेहनतकशों की जीविका व काम के हालातों पर हो रहे हमलों के खिलाफ उनके असंतोष की अभिव्यक्ति है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में ऊपर की ओर रूख के दावों के बावजूद, मजदूरों की दशा में कोई सुधार नहीं हुआ है। बहुत से देशों में युवा बेरोजगारी चिंताजनक स्तर पर बनी हुई है। यहाँ तक विश्व अर्थव्यवस्था में उभार की बात करने वाले विश्व बैंक को वैश्विक आर्थिक संकट की शुरूआत के बाद से पहली बार यह चेतावनी देने के लिए बाध्य होना पड़ा है कि यह उभार थोडे समय के लिए है और इसमें लोगो के जीवन स्तर में सुधार या गरीबी धटने की ज्यादा संभावना नहीं है। कई अर्थशास्त्रियों की राय है कि संकट का एक और चक्र भी शुरू हो सकता है।

गैरबराबरी अशिष्टता के स्तर पर पहुँच गई है। जनवरी 2018 में जारी औंक्सफेम रिपोर्ट के अनुसार 2017 में पैदा हुई कुल वैश्विक दौलत का 82 प्रतिशत सिर्फ 1 प्रतिशत लोगों की मुट्ठी में था जिनके पास आज दुनिया की कुल दौलत का आधे से ज्यादा है। भारत में ऊपर के 1 प्रतिश के पास 2017 में देश में मेहनतकश जनता द्वारा पैदा की गई दौलत का 73 प्रतिशत है। दुनिया के सबसे धनी 42 लोगों के पास उतनी दौलत है जितनी 2017 में आधे सबसे गरीबों के पास थी।

दौलत का कुछ लोगों के पास संकेन्द्रण कोई उनकी असाधारण प्रतिभा, मेहनत या नवाचारों के कारण नहीं है जैसा कि बहुत से लोगों को विश्वास दिलाया जाता है। ऑक्सफेम रिपोर्ट यह स्पष्ट करती है कि ऐसा उत्तराधिकार, एकाधिकार, दरबारवाद, करचोरी और सबसे बढ़कर मजदूरों के शोषण के चलते है। इन नीतियों के कारण बेरोजगारी विशेषकर युवाओं के बीच बेरोजगारी चिन्ताजनक स्तर पर है। भारत में स्नातकों व उसके अधिक पढ़े–लिखे की बेरोजगारी दर 23.8 प्रतिशत पर पहुँच गई है। रोबोटिक्स, आर्टीफीशियल इटेंलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आदि का उपयोग काम के घंटो को कम करने या मजदूरों के बोझ को कम करने के लिए नहीं बल्कि इस प्रोद्योगिकी के मालिक बड़े कारपोरेशनों व व्यापारिक घरानों के मुनाफे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है।

नवउदारवादी नीतियों के दुष्प्रभावों के खिलाफ लोगों के इस असंतोष को कई सारे देशों में सही दिशा में नहीं मोड़ा जा रहा है। इसका इस्तेमाल दक्षिणपंथी ताकतों द्वारा किया जा रहा है। ऐसा विशेषकर उन देशों में हो रहा है जहाँ वाम ताकतों व सोशल डेमोक्रेटिक पार्टियों ने नउदारवाद की ओर पाला बदलते हुए उस मेहनतकश जनता के साथ विश्वासधात किया है जिन्हें वह पहले समर्थन देते थे। परम्परागत वाम व सोशल डेमोक्रेटिक पार्टियाँ जो सत्ता में रहते नवउदारवादी नीतियों को लागू करती रहीं उन्हें जनता द्वारा नकारा जा रहा है। दक्षिणपंथी ताकतें लोगों के असंतोष का इस्तेमाल कर उसे नस्ल, धर्म, लिंग आदि आधारों पर मेहनकशों के अन्य तबकों के विरूद्ध प्रयोग कर रही हैं। वे जनता की एकता को छिन्न–भिन्न कर नवउदारवादी नीतियों के विरूद्ध लड़ाई को कमजोर करती हैं। जब वे सत्ता में आती हैं तो वो उन्हीं नीतियों को लागू करती हैं। कई यूरोपीय देशों जैसे इटली, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस व स्केनडेनिवेयिन देशों में ऐसा देखा गया है।

इसके साथ ही, जहाँ भी वामपंथियों ने नवउदारवादी नीतियों के खिलाफ मजदूरों के संधर्षो का समर्थन या उनका नेतृत्व किया है वहाँ वाम को फायदा हुआ है जैसा कि ग्रीस, पुर्तगाल, स्पेन में और जेरेमी कोरबीन के नेतृत्व में इग्लैंड में लेबर पार्टी के बढ़ते प्रभाव, अमेरिका में डेमोक्रटिक सोशलिस्ट्स की बढ़ती लोकप्रियता विशेषकर युवाओं में, आदि में देखने में आया है।

आज मजदूर वर्ग और मेहनतकश लोग विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। कार्ल मार्क्स की महान कृति 'पूंजी' में लोगों का विशेषकर युवाओं की रूचि बढ़ी है जो पहली बार 150 वर्ष पहले प्रकाशित हुई थी। विश्व की एकमात्र वर्गीय रूप से उन्मुख वैश्विक ट्रेड यूनियन–वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस का प्रभाव भी सारे विश्व में बढ़ रहा है।

पूंजीवाद का सबसे नया चरण–नवउदारवाद पूरी तरह से अपनी साख खो चुका है और वह टिके रहने की स्थिति में नहीं है। लेकिन, यह समझना जरूरी है कि पूंजीवादी व्यवस्था अपने आप में संकट से मुक्त नहीं हो सकती है। एक दशक पुराना यह वैश्विक आर्थिक संकट इस श्रंखला की नवीनतम कड़ी है। प्रत्येक संकट में पूंजीपति, मेहनतकशों पर ज्यादा बोझ डालकर अपने मुनाफे को बचाने की कोशिश करते हैं जिसके कारण मेहनतकशों की क्रय शक्ति घट जाती है। इसके पहले कि विश्व 2008 के संकट से बाहर निकलता एक और संकट की आशंकायें व्यक्त की जा रही हैं। ऐसी परिस्थिति में, अंतर्राष्ट्रीय वित्त को यह जरूरी लगता है कि दक्षिणपंथी शक्तियों को बढ़ावा दे जो मजदूर वर्ग और जनता को नस्ल, धर्म, क्षेत्र, लिंग, भाष आदि के आधार पर बांटना चाहती हैं तथा मेहनतकश जनता की एकता को तोड़कर नवउदारवादी नीतियों के विरूद्ध संधर्ष को कमजोर करती हैं। भारत समेत अब यह विश्वव्यापी स्थिति हो गयी है जैसा कि भाजपा और मोदी को बड़े कारपोरेशनों ने चाहे देशी हो या विदेशी के द्वारा हर तरह की मदद व संसाधन प्रदान करने के रूप में देखा जा रहा है।

अमरीकी साम्राज्यवाद, वाम ताकतों को दबाने व नवउदारवादी नीतियों के विरूद्ध प्रतिरोध को दबाने के लिए लातीनी अमरीका व अन्य देशों की प्रगतिशील व वाम झुकाव वाली सरकारों को हिलाने–गिराने के लिए हस्तक्षेप करने में अपनी सामरिक व राजनीतिक ताकत के इस्तेमाल की कोशिश कर रहा है ताकि वह इन देशों के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों पर नियन्त्रण हासिल कर सके। एक ओर तो अमरीकी साम्राज्यवाद 'आतंक से लड़ने' की बात कर रहा है; वहीं दूसरी ओर यह वित्तीय व अन्य तरह की मदद कर आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा दे रहा है। भाजपा के शासन में भारत, देश की लम्बे समय से चली आ रही स्वतंत्र विदेश नीति को छोड़कर अमरीका का जूनियर रणनीतिक साझीदार बन गया है।

इस परिस्थिति में यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि 2008 में वैश्विक आर्थिक संकट के शुरू होने से ही चीन ने धरेलू माँग को बढ़ाने के लिए न्यूनतम वेतन में वृद्धि करने, ग्रामीण व शहरी गरीबों को आवास प्रदान करने आदि जैसे कई कदम उठाये हैं। इनके चलते व्यक्तिगत प्रतिव्यक्ति खर्च की जाने वाली आय बढ़ी है, दशकों में बेरोजगारी अपने न्यूनतम स्तर पर पहुँच गई है और 6 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आये हैं। चीन अपने आपको एक विकसित विर्निमाता देश में बदल रहा है और उसका ध्यान सूचना प्रोद्योगिकी, रोबोटिक्स, एयरोस्पेस, रेलवे, इलैक्ट्रिक वाहनों आदि पर केन्द्रित है। हाल ही में संपन्न हुई नेशनल पीपुल्स काँग्रेस में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने धोषणा की है कि 'इतिहास सिद्ध कर चुका है और आगे भी करेगा कि केवल समाजवाद ही चीन को बचा सकता है।' न केवल चीन, बल्कि केवल समाजवाद ही विश्व को बचा सकता है।

महासचिव की रिपोर्ट में भाजपानीत मोदी सरकार के शासन में मजदूर वर्ग और मेहनतकशों के अन्य तबकों के हालातों को स्पष्ट रूप से सामने रखा गया है। इसमें सरकार की घरेलू नीति के तीन प्रमुख पहलुओं–नवउदारवादी नीतियों पर आक्रामक अमल, आर एस एस के साम्प्रदायिक व विभाजनकारी हिन्दुत्व के एजेंडे को खुला समर्थन और बढ़ते सत्तावादी रूझान को रेखांकित किया गया। मजदूर वर्ग के आंदोलन को अपनी एकता को बचाने और नवउदार नीतियों के विरूद्ध संधर्ष को तेज करने के लिए इन तीनों के विरूद्ध एक साथ ही लड़ना होगा।

महासचिव की रिपोर्ट में नोटबंदी, जी एस टी, केन्द्रीय बजट 2018–19 तथा सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं समेत उसके धोखा देने वाले नारों व पहलुओं का पर्दाफाश किया गया। इन सभी का प्रयोग मेहनकशों द्वारा अपने खून–पसीने से पैदा धन का देशी–विदेशी बडे कारपोरेटो को हस्तांतरण करने के लिए किया जा रहा है। जहाँ बड़े पूंजीपति व जमींदार वर्ग को भारी रियायतें दी गयी हैं वहीं मजदूरों व आम जनता पर भारी बोझ डाल दिया गया है जिनके हालात बदतर हुए हैं और जिनकी आय घटी है। सार्वजनिक क्षेत्र को तहस–नहस किया जा रहा है। कोयला खदानों को निजी व्यवसायिक कोयला खनन के लिए खोल दिया गया है। भाजपा सरकार जो, चूकती, राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुँचाते हुए रक्षा व रेलवे जैसे रणनीतिक क्षेत्रों का निजीकरण कर रही है। द् फाइनेंशियल रिजोल्यूशन एंड डिपोजिट इन्श्योरेंस बिल (एफ आर डी आइ) 2017 में कर्ज का भुगतान न होने के लिए वित्तीय संस्थाओं को तो कटघरे में खड़ा किया गया है लेकिन कर्ज अदा न करने वाले कारपोरेटों को कुछ नहीं कहा गया। इससे एक ओर इन संस्थाओं के निजीकरण का रास्ता साफ होगा और बैंको के दिवालिया हो जाने पर आम जनता का बैंकों में जमा धन खतरे में पड़ जायेगा।

श्रम कानूनों में संशोधनों के अतिरिक्त, जिनके बारे में कई बार चर्चा की जा चुकी है, सरकार ने हाल ही में ठेका श्रम अधिनियम में संशोधन किया है और उसमें ठेका श्रमिकों के बचाव के लिए जो कुछ था उसे हटा दिया है। स्थायी और बराबर चलने वाले प्रकृति के रोजगार की पूरी अवधारणा को ही 'कोर व पैरीफीरल जॉब्स' में बदला जा रहा है। इस प्रकार स्थायी प्रकृति का कार्य काने वाला एक मजदूर नियमित होने का दावा नहीं कर सकता है। इसी तरह, एक ऐसी ऐजेंसी के लिए कार्य करने वाले मजदूर जिसे एक विशेष कार्य आऊटसोर्स किया गया है, उन्हें ठेका मजदूर नहीं माना जायेगा और ऐसे मामले में श्रम कानूनों की पालन के बारे में प्रमुख नियोक्ता की कोई जिममेदारी नही होगी। संशोधित एक्ट के क्रियान्वयन के उल्लंधन के संबंध में पेनल्टी को कम से कम कर दिया गया है। सरकार ने भारी विरोध के बावजूद एक अधिसूचना के जरिये तय अवधि के रोजगार की भी शुरूआत की है। इस कदम को पहले 2002 में तब की वाजपेयी के नेतृत्व वाली एन डी ए सरकार लेकर आयी थी जिसे ट्रेड यूनियन ओदोलन व वामपंथी दलों के दबाव में 2007 में यू पी ए सरकार को रद्द करने पर बाध्य होना पड़ा था। यह सारी प्रक्रिया मजदूरों की कीमत पर सरकार के 'ईज ऑफ डूईंग बिजनेस इंडेक्स' को सुधार ने के लिए है।

दलितों व अल्पसंख्यकों विशेषकर मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं; बड़े कारपोरेट पशु व्यापारियों को लाभ पहुँचाने के लिए उनकी जीविका पर तथाकथित 'गौरक्षकों' द्वारा हमले किये जा रहे हैं। साम्प्रदायिक संगठन आम जनता के रोजमर्रा जीवन को नियन्त्रित करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए उन्हें क्या खाना है, क्या पहनना है, किससे मेल–जोल रखना या शादी करनी है आदि के फरमान सुना रहे हैं। वे शारीरिक हमलों, ब्लैक मेलिंग व डराने–धमकाने के माध्यम से असहमति या विरोध की सभी आवाजों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं।

सरकार 'धन विधेयकों' के नाम पर अधिसूचनायें आदि जारी कर राज्य सभा को, बाईपास करते हुए सत्तावाद पर उतरी हुई है। जहाँ वह अपने आपको सुपर राष्ट्रवादी कहती है वहीं वह रेलववे व रक्षा समेत निजीकरण्र के राष्ट्र विरोधी कदम उठा रही है और हमारे प्राकृतिक संसाधनों को देशी–विदेशी निजी हाथों में सौंप रही है।

इस संदर्भ में, मजदूरों, किसानों, छात्रों, दलितों व समाज के अन्य तबकों के संधर्षो का एक उभार आया है विभिन्न सैक्टर वार संधर्षो और अभूतपूर्व संयुक्त ट्रेड यूनियन 'महापड़ाव' इसकी गवाही देता है।

जनरल कौसिंल ने तपन सेन द्वारा पेश किये गये संगठन के अद्यतन दस्तावेज और हेमलता द्वारा पेश भविष्य के ठोस कामों को भी पारित किया। इनमें संयुक्त ट्रेड यूनियन आंदोलन की 12 सूत्री मांगों, सीटू सचिव मंडल द्वारा पारित 10 सूत्री मांगो तथा मजदूरों व मेहनतकशों के अन्य तबकों के स्थानीय मुद्दों व मांगों के काम व जीवन के हालातों से जुड़ मांगों पर व्यापक व सधन स्वतंत्र अभियान के बाद 5 सितम्बर, 2018 को दिल्ली में कम से कम 2 लाख मजदूरों की लामबंदी करना भी शामिल है। किसानों, खेतमजदूरों, दलितों, आदिवासियों महिलाओं, युवाओं, छात्रों व अल्पसंख्यकों की मांगों को भी इस अभियान में मौजूदा जनवादी नीतियों के विरोध में वैकल्पिक जन–हितैषी नीतियों को सामने रखने पर केन्द्रित होगा।

संगठन पर अद्यतन इस्तावेज को संगठन में जमीनी स्तर तक ले जाने, इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा 'जिन तक नहीं पहुँचे, उन तक पहुँचो' के सीटू के नारे को तथा मुद्दों को नीतियों से और नीतियों के पीछे की राजनीति को बेनकाब करने के स्वतंत्र अभियान पर अमल के लिए एक विस्तृत योजना को भी जनरल कौंसिल द्वारा पारित किया गया।

जनरल कौंसिल ने जन एकता जन अधिकार आंदोलन (जे इ जे ए ए) के आहवान पर 23 तारिख के विरोध प्रदर्शन में मजदूरों की लामबंदी करने, इसके पहले चलने वाले एक सप्ताह के अभियान में सक्रिय भागेदारी करने, मजदूरों की मांगों को उठाते हुए ए आइ के एस के आहवान पर 9 अगस्त, 2018 के जिला स्तर पर गिरफ्तारियां देने के आहवान में भाग लेने तथा 14 अगस्त को रात को सामूहिक जागरण कार्यक्रम करने का भी फैसला किया है। जनरल कौंसिल ने इस इौरान संयुक्त ट्रेड यूनियन आंदोलन द्वारा तय किये जाने वाले कार्यक्रम में भी प्रभावी भागेदारी करने का फैसला लिया है।

मोदी सरकार द्वारा सभी सैक्टरों में तय अवधि रोजगार की शुरूआत करने के विरोध में

केरल में संयुक्त हड़ताल के समर्थन में

केरल के कोझिकोड में 23–26 मार्च, 2018 तक हो रही सीटू की यह जनरल कौंसिल बैठक;

– केरल की कामकाजी जनता व उसके नेतृत्व को, केन्द्रीय व राज्य ट्रेड यूनियनों–इंटक, एटक, एच एम एस, सीटू, यू टी यू सी, ए आइ यू टी यू सी, टी यू सी सी, सेवा, एस टी यू, एच एम पी के, टी यू सी आइ, ए के टी यू, के टी यू सी, के टी यू सी (जे), के टी यू सी (एम), आइ एन एल सी की राज्य इकाईयों को, मजदूरों को कारपोरेटों की मरजी का गुलाम बनाने वाले और काम की स्थायी प्रकृति को समाप्त कर सभी सैक्टरों में तय अवधि के रोजगार की शुरूआत करने वाली भारत सरकार की क्रूर अधिसूचना के विरोध में 2 अप्रैल, 2018 की राज्यव्यापी हड़ताल के लिए बधाई देती है;

– इस कदम के विरूद्ध जो बड़े कारपोरेटों की जरूरतों को पूरा करने वाली नवउदारवादी नीतियों पर अमल का एक हिस्सा है, हर कीमत पर लड़ना होगा और इस संदर्भ में केरल राज्य के पुरूष व महिलओं का फैसला समूची भारतीय जनता में एक नया जोश पैदा करेगा जो भारत सरकार की जन–विरोधी नीतियों के खिलाफ जुझारू संधर्षों के मैदान में है;

यह जनरल कौंसिल बैठक, सभी संबद्धो, बिरादराना संगठनों व सीटू राज्य समितियों से केरल में 2 अप्रैल को होने वाली हड़ताली कार्रवाई की एकजुटता में उसी दिन विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का आहवान करती है।

केन्द्र सरकार से 'तय अवधि रोजगार' अधिसूचना को वापस लेने की माँग करते हुए

केरल में २ अप्रैल की हड़ताल : एक ऐतिहासिक सफलता

इलामारम करीम

केरल के मजदूरों ने स्थायी रोजगार के स्थान पर तय अवधि का रोजगार शुरू करने वाली केन्द्र सरकार की अधिसूचना को वापस लिये जाने की माँग करते हुए 2 अप्रैल को 24 घंटे की राजव्यापी हड़ताल की। बी एम एस को छोड़कर सभी ट्रेड यूनियनों की ओर से हड़ताल का आहवान किया गया। सभी तबकों के समर्थन के साथ यह हड़ताल एक आम हड़ताल बन गई और पूरा राज्य जैसे ठहर गया।

राज्य में हड़ताल एक ऐतिहासिक सफलता बनी। सभी व्यावसायिक दुकानें बेद रहीं, सड़कों पर केवल कुछ दुपहिया व निजी वाहन ही निकले। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के सभी मजदूर हड़ताल में शामिल हुए।

कोचीन पोर्ट, वलारपदम कंटेनर टर्मिनल, अलूवाकलामाशेरी औद्योगिक क्षेत्र, कंचिकोड़, औद्योगिक क्षेत्र, स्पेशल इकॉनामिक जोन, टेक्नो पार्क, इन्फो पार्क आदि जो आइ टी सैक्टर में आते है में भी हड़ताल रही। औद्योगिक केन्द, प्लांटेशनों, परम्परागत रोजगार क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र पूरी तरह से बंद रहे। प्रेस वर्कर्स यूनियन भी हड़ताल में शामिल हुई और मार्च में भाग लिया। बिजली बोर्ड, जल प्राधिकरण, परिवहन निगम आदि जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपक्रमों में भी पूर्ण हड़ताल रही। वी एस एस सी, कोचीन शिपयार्ड, इंस्ट्रमेंटेशन, बी एस एन एल आदि जैसे केन्द्र सरकार के संस्थानों में काम ठप्प रहा। शिक्षण संस्थान, सहकारी क्षेत्र, निजी व सार्वजनिक बैंक, स्थानीय निकाय, डाक संवायें आदि बंद रही। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र संगठनों में काम करने वाले बी एम एस कर्मचारियों ने भी काम न करके हड़ताल में सहयोग किया।

हड़ताली मजदूरों ने थिरूवनंतपुरम में मार्च निकाला और राजभवन के सामने धरना दिया। अन्य सभी जिलों में मार्च व धरने केन्द्र सरकार के दफ्तरों के सामने किये गये।

राजभवन मार्च का उद्धाटन सीटू के राज्य अध्यक्ष अनंतलावत्तम आनंदन ने किया। इंटक के राज्य अध्यक्ष आर चन्द्रशेखरन, एटक के राज्य महासचिव के पी राजेन्द्रन, यू टी यू सी के राज्य नेता शिबु बेबीजॉन, सीटू राज्य सचिव वी शिवन कुट्टी, व अन्य शामिल रहे। लगभग 15000 मजदूरों ने इसमें भाग लिया।

हड़ताल के पूर्व अभियान के लिए जिला/इलाका वार प्रचार मार्च आयोजित किये गये थे। ट्रेड यूनियनों ने सभी संस्थाओं को संयुक्त नोटिस दिये। सभी जिलों में प्रेस कॉफ्रेस व पोस्टर प्रचार किया गया था। संयुक्त ट्रेड यूनियनों के सदस्यों ने परचे बांटे और दुकानदारों से व्यापारियों से हड़ताल में भाग लेने का अनुरोध किया। मजदूरों ने 1 अप्रैल की शाम को मशाल जुलूस निकाले। विभिन्न जिलों में आंदोलन का नेतृत्व ट्रेड यूनियनों के नेताओं द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

थोड़े समय के अन्दर ही हड़ताल की सफलता के लिए बहुत ही कारगर काम किया गया था। जनता ने हड़ताल को भारी समर्थन दिया। यह हड़ताल मोदी सरकार की धोखा नीति को एक चेतावनी थी। हड़ताल का समाज के सभी तबकों की ओर से स्वागत हुआ।

परिपत्र 4

1• प्रकाशन का पता : बी टी रणदिवे भवन
13–ए राऊ एवेन्यू
नई दिल्ली–110002

2•प्रकाशन की अवधि : मासिक

3• मुद्रक का नाम : तपन सेन
क्या भारत का नागरिक हैं : हाँ
पताः : बी टी रणदिनवे भवन
13–ए राऊज एवेन्यू
नई दिल्ली–110002

4• प्रकाशक का नाम : तपन सेन
क्या भारत का नागरिक है : हाँ

5• संपादक का नाम : के हेमलता
क्या भारत का नागरिक हैं : हाँ

6• कुल पूंजी के एक प्रतिशत से ज्यादा के हिस्सेदारों का नाम पता : सेंटर ऑफ इंडियन
13–ए, राऊ एवेन्यू
नई दिल्ली–110002

हस्ताक्षर
तनप सेन
प्रकाशक

महाराष्ट्र में किसानों का ऐतिहासिक 'लाँग मार्च'

फडनवीस सरकार ने 95 प्रतिषत माँगे मानीं

महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में किसानों की आत्महत्याओं का कारण बने कृषि संकट के खिलाफ संधर्ष के एक अनोखे रूप में आग बरसाते सूरज के तले अखिल भारतीय किसान सभा के मजदूरों व किसानों की एकता के प्रतीक हंसिया हथौड़े वाले लाल झंडे के नीचे महिलाओं बुजुर्गो समेत जिनमें बड़ी संख्या में आदिवासी व गरीब थे, करीब 25000 किसानों ने 6 मार्च को नासिक से मुंबई की ओर 200 किलोमीटर लम्बी कठिन यात्रा वाला ऐतिहासिक 'किसान लाँग मार्च' शुरू किया। जैसे–जैसे यह लम्बा कूच आगे बढ़ा इसमें और ज्यादा किसान शामिल होते गये और उनकी तादाद बढ़ती गयी।

प्रारम्भ में, भाजपा नेताओं व फडनवीस सरकार ने किसानों के 'लाँग मार्च' की खिल्ली उड़ायी और संधर्षरत किसानों को 'उग्रवादी' बताया था। लेकिन थकान, निर्जलन, कमजोरी व हजारों किसानों खास तौर पर बुजुर्गों के पाँवों में छालों के बावजूद जैसे–जैसे निश्चयी व अनुशासित मार्च आगे बढ़ता गया, उसे प्रदेश व भारत भर में जनता के बीच एक सहानुभूति की लहर पैदा की; प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में लीड स्टोरी के लिए होड़ लग गई; विधान सभा के अन्दर व उसके बाहर विपक्ष व भाजपा सहयोगी समर्थन में आये; भाजपा नेताओं को अपने बचाव के लिए भागना पड़ा और मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ए आइ के एस द्वारा उठायी गयी माँगो के प्रति 'संवदेनशील व सकारात्मक' है। इस लाँग मार्च को जनता का तब और भी समर्थन मिला जब मंजिल पर पहुँचने के अेतिम चरण के लिए किसानों ने परीक्षा के लिए बच्चों के आवागमन में किसी भी तरह की बाधा न पहुँचे यह ध्याान में रखते हुए मंबई शहर में रात में मार्च करने का फैसला लिया।

12 मार्च को, 50,000 किसानों का यह ऐतिहासिक लाँग मार्च, उस स्थिति में कि फडनवीस सरकार उनकी वाजि माँगों को मानने से इनकार करे तो अपनी आखिरी मंजिल राज्य विधान सभा के सामने पहुँचने से पहले मुबंई के ऐतिहासिक आजाद मैदान में प्रविष्ट हुआ।

ए आइ के एस प्रतिनिधिमंडल और फडनवीस सरकार के मंत्रियों की समिति के बीच ए आइ के एस की सभी माँगो पर 3 धंटे किसान नेता व महाराष्ट्र विधान सभा में सी पी आइ (एम) के लगातार सात बार से विधायक जे पी गावित की माँग के अनुरूप सरकार ने बातचीत के लिए तीन पूर्व शर्तो को स्वीकार किया–बातचीत का ब्यौरा दर्ज किया जायेगा, समझौता लिखित होगा जिसे विधायी रिकार्ड का हिस्सा बनाने के लिए विधान सभा में रखा जायेगा। अंतत : सरकार ने लगभग वे सभी माँगे मान लीं जो न्यायोजित, तार्किक व सही थीं। सरकार की ओर से मुख्य सचिव ने समझौते पर दस्तखत किये। जैसी कि पहले सहमति बनी थी, समझौते की लि,ित प्रतिलिपि को अगले दिन ''किसानों के लाँग मार्च'' पर चर्चा के दौरान विधान सभा में रखा गया। किसानों व आदिवासियों के प्रतिनिधियों के बीच आज विधान भवन में एक बैठक हुई। हम सहमत हैं कि आदिवासियों को कृषि भूमि आवंटित करने के लिए कमेटी का गठन होगा यदि किसान 2005 से पूर्व जमीन जोतने का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं तो। हमने उनकी लगभग सभी माँगे मान ली हैं, फडनवीस ने प्रेस को बताया।

सरकार की तरफ से, राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने आजाद मैदान पहुँचकर, सी पी आइ (एम) महासचिव सीताराम येचुरी की उपस्थिति में, जो किसान रैली में मौजूद थे, ऐलान किया कि समझौते में सरकार ने किसानों की सेभी माँगे मान ली हैं।

विपक्षी काँग्रेस, एन सी पी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिव सेना भी जो राज्य में और केन्द्र में भाजपानीत सरकारों का हिस्सा है, किसानों के आंदोलन व मांगों का समर्थन किया। एम एन एस प्रमुख राल ठाकरे व शिव सेना नेता आदित्य ठाकरे भी आजाद मैदान में किसानों से मिले।

येचुरी ने अपने संबोधन में किसानों को 'भारत के नये सिपाही' बताया जो यदि उनकी माँगे नहीं मानी गयीं तो सरकारों को उखाड़ सकते हैं। ए आइ के एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. अशोक धवले व ए आइ के एस के राज्य नेताओं ने आजाद मैदान में किसान रैली का नेतृत्व किया व संबोधित किया। सीटू के नेता डा. डी एल कराड भी मार्च में शामिल हुए और रैली को संबोधित किया।

इस शानदार जीत के साथ लाँग मार्च में शामिल किसान की घर वापसी की यात्रा शुरू हो गई। मध्य रेलवे ने उन्हें ले जाने के लिए मुंबई से भुसावल तक विशेष रेलगाड़ी चलाई। ऐसा था इस संधर्ष का प्रभाव।

फड़नवीस सरकार द्वारा लिखित रूप में स्वीकार की गईं ए आइ के एस की माँगों में, कमी सुधार के साथ बिना शर्त कर्ज माफी; वन अधिकार कानून के तहत आदिवासियों व परम्परागत वन निवासियों को वन जमीन का हस्तांरण; स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के अनुसार किसानों को उनकी उपज का लागत से डेढ़ गुना लाभकारी मूल्य; नासिक, ठाणे, पालघर में नदी जोड़ो परियोजना में बदलाव कर बड़े बांधो के स्थान पर छोटे बांध ताकि आदिवासियों की जमीन को डूबने से बचाया जा सके तथा पानी को गुजरात के बजाय महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त जिलों की ओर मोड़ने; हाई स्पीड रेल व सुपर हाइवे आदि परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण पर रोक की माँगे शामिल है

बधाईयों वाले बयान

सीटू ने महाराष्ट्र के किसानों को बधाई दी

13 मार्च को जारी एक बयान में, मुश्किल हालातों में निकाले गये ऐतिहासिक 'किसानों के लंबे कूच' के लिए और अपनी सभी जायज मांगो को मानने के लिए राज्य की भाजपा सरकार को मजबूर करने वाली विस्तृत जीत के लिए सीटू ने महाराष्ट्र के किसानों को बधाई दी।

सीटू ने, महाराष्ट्र व अन्य राज्यों में किसानों के सफल संधर्षो का नेतृत्व करने तथा संयुक्त किसान संधर्षो के लिए पहलकदमी करने के लिए अखिल भारतीय किसान सभा को बधाई दी। ये संधर्ष, राजस्थान में पहले हुए संधर्ष की तरह ही निराशा में आत्महत्या के स्थान पर किसानों द्वारा संधर्ष के रास्ते पर आने के सूचक हैं।

मजदूर वर्ग, संधर्षरत किसानों के साथ अपनी एकजुटता के साथ खड़ा है। सीटू, किसानों की मांगों के संधर्ष व एकजुटता में मजदूर वर्ग के समर्थन को जारी रखने के लिए प्रतिवद्ध है।

वुफ्टू ने महाराष्ट्र के विजयी किसानों को बधाई दी

WORLD FEDERATION OF TRADE UNIONS

Class oriented - uniting - democratic - modern – independent – internationalist!

Athens, 14th March 2018

वुफ्टू, भारत में महाराष्ट्र के किसानों के विजयी संधर्ष को बधाई देती है

पाँच महाद्वीपों में अपने 9 करोड़ 20 लाख सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, अपनी जायज मांगो के लिए संधर्षरत दसियों हजार किसानों के जुझारू ग्रेट मार्च में शामिल होने पर उन्हें बधाई देती है।

ग्रेट मार्च, 6 मार्च को शुरू हुआ जिसमें किसानों ने नासिक से मुंबई कूच किया। ग्रेट मार्च के 200 किलोमीटर के रास्ते में जगह–जगह जन सभायें व एकजुटता अभियान हुए। यह प्रभावशाली मार्च, सरकार को किसानों की मांगों को लिखित रूप में स्वीकार करने के लिए मजबूर करने के उपरान्त ही सम्पन्न हुआ।

वर्गीय रूप से उन्मुख ट्रेड यूनियन आंदोलन स्वीकार की मांगों के त्वरित क्रियान्वयन की माँग करता है जिससे हजारों किसानों जीवन व काम के हालातों में सुधार आयेगा। यह संधर्ष, समूची दुनिया में जनता को रास्ता दिखाने वाले विजयी संधर्षो की अंतहीन सूची में जुड़ गया है।

सी पी आइ (एम) पोलिट ब्यूरो ने महाराष्ट्र के किसानों को बधाई दी

सी पी आइ (एम) के पोलिट ब्यूरो ने 16–17 मार्च की अपनी बैठक में महाराष्ट्र में किसानों के आंदोलन को नोट किया और वन अधिकार कानून के क्रियान्वयन, लाभकारी मूल्य व पेंशन; कर्जदार किसानों के लिए कर्जमाफी आदि के लिए अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में नासिक से मुंबई तक के उनके लम्बे कूच (लाँग मार्च) की भारी सफलता के बाद माँगे मनवाने में मिली सफलता पर उन्हें बधाई दी।

बयान में कहा गया, ''कि मार्च ने महाराष्ट्र की सरकार को किसानों की माँगो को मानने और लिखित आश्वासन देने के लिए बाध्य किया। इसका राष्ट्रव्यापी असर हुआ है। अब यह महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह एक समय बद्ध तरीके से अपने वादों को पूरा करे।''

पोलिट ब्यूरो ने महाराष्ट्र की जनता के सभी तबकों तथा राजनीतिक व सामाजिक आन्दोलनों के व्यापक घटकों से लाँग मार्च को मिले समर्थन की भी प्रशंसा की।

महाराष्ट्र में किसान सभा का लॉन्ग मार्च एक शानदार जीत के साथ समाप्त

अशोक धवले

यह वास्तव में एक अद्भुत संघर्ष था, वैसा अभी हाल ही के दिनों में महाराश्ट्र में देखने में नहीं आया है। यह किसानों और जनता की कल्पना पर छा गया और न केवल राज्य में बल्कि पूरे देश में उनका अघोशित समर्थन भी प्राप्त किया। इसे राजनीतिक विस्तार भर में पार्टियों और संगठनों का समर्थन प्राप्त हुआ। 6 से 12 मार्च तक के सप्ताह भर लगभग 200 किलोमीटर तक का लॉन्ग मार्च, पूरे राष्ट्रीय और राज्य मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों के लिए आकर्शण का केंद्र बन गया, और सोशल मीडिया में भी हैशटैग किसान लॉन्ग मार्च 12 को पूरे दिन के अखिल भारतीय हैशटैग में सर्वप्रथम का रुझान दिखा रहा था।

नासिक से हजारों किसान महिलाओं सहित 25 हजार से अधिक किसानों की एकजुटता से शुरु होकर, मुंबई में 50,000 से अधिक किसानों के साथ संपन्न हुआ। किसान सभा के लाल झंडे, लाल बैनरों, लाल टोपियों और मुख्य मांगों पर प्रकाश डालने वाले लाल प्लैकाडर्स् आदि ने इस लम्बे मार्च को लाल रंग का विशाल सागर बना दिया। ए.आई.के.एस. के पूर्व अध्यक्ष एवं विधायक जे पी गावित के प्रेरणादायक नेतृत्व के तहत नाषिक जिले के हजारों आदिवासी किसानों की अब तक की यह सबसे बड़ी लामबन्दी थी। आगे यह ठाणे–पालघर जिले से था, उसके बाद अहमदनगर जिले से था। राज्य के कई अन्य जिलों ने भी प्रतिनिधित्व किया था, जो इस लॉन्ग मार्च के आखिर के दो दिनों में स्पष्ट रूप से उभरकर आया था।

यह लॉन्ग मार्च महाराश्ट्र में ए.आई.के.एस. की अगुवाई में तीन साल के निरंतर संघर्ष की परिणति थी, लॉन्ग मार्च के लिए सावधानीपूर्वक तैयारी, आखिरी विवरण के साथ अपनी रसद की योजना सहित, ए.आई.के.एस. के सामूहिक राज्य नेतष्त्व द्वारा आयोजित किया गया था, जो 16 फरवरी से ही जब सांगली में ए.आई.के.एस. राज्य परिशद की विस्तारित बैठक में निर्णय लिया गया था। प्रतिभागियों के

भोजन के लिए अनाज, तेल और ईधन को स्वयं गांवों से एकत्र किया गया था। पीने के लिए पानी के टैंकरों को रास्ते में विभिन्न बिंदुओं पर तैनात किया गया था। एक डॉक्टरों की टीम और आवष्यक दवाइयों के साथ एक एम्बुलेंस को लॉन्ग मार्च के साथ रखा गया था।

जिस तरह से हजारों गरीब और भूमिहीन किसानों ने अपने नेताओं के साथ सूरज की तेज गर्मी में सात दिन तक 30 से 40 किलोमीटर प्रति दिन दृढ़ संकल्प के साथ मार्च में सैकड़ों ने जूते के बिना तारकोल की सड़कों पर, घायल और खून बहते पैर देखकर, बड़े पैमाने पर जनता ने न केवल उनके मकसद का समर्थन किया, बल्कि बीजेपी की अगुवाई वाली कठोर और असंवेदनशील सरकार के खिलाफ भी बड़े पैमाने पर जनता में भारी क्रोध था।

यह सब मजदूर वर्ग, मध्य वर्ग, दलित, मुस्लिम, सिखों और मुंबई और ठाणे शहर के अन्य सभी वर्गों से भारी प्रतिक्रिया में साफ तौर पर परिलक्षित हुआ। लॉन्ग मार्च को कई इलाकों में खुली बाहों के साथ केवल स्वागत नहीं किया गया, बल्कि इन दोनों शहरों में जनता ने नकदी और दयालुता दोनों में उदारता से दान किया। मुंबई और ठाणे–पालघर जिले में सीटू, एडवा, डी.वाई.एफ.आई. और एस. एफ.आई. ने इस लॉन्ग मार्च के समर्थन में लोगों के बीच बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया, लेकिन जन प्रतिक्रिया इससे कहीं ज्यादा दूर तक थी।

अंतिम दिन ए.आई.के.एस. के शानदार मानवीय निर्णय कि ठाणे शहर से 11 मार्च से 11 बजे सुबह से 12 मार्च को सुबह 6 बजे तक दिन और रात चलकर 12 मार्च को मुंबई शहर बीच में आजाद मैदान तक पहुँचना ताकि मुंबई में हजारों एसएससी छात्रों की बोर्ड की अंतिम परीक्षाओं में बाधा से बचा जा सके की पूरे देश में लोगों ने भूरि–भूरि प्रशंसा की। भारत में कई प्रमुख हस्तियों ने भी इस भावना पर अपनी प्रशंसा व्यक्त की।

इस सब का भाजपानीत राज्य सरकार पर जबरदस्त दबाव पड़ा। 12 मार्च को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्रियों चंद्रकांत पाटिल, गिरीश महाजन, एकनाथ षिंदे, पांडुरंग निधिकर, सुभाश देषमुख और विश्णु सावरा ने विभिन्न विभागों के षीर्श अधिकारियों के एक समूह के साथ में किसान सभा के नेताओं के साथ तीन घंटे की चर्चा विधान भवन में आयोजित की। चर्चा के दौरान भी विपक्षी दलों के नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल (कांग्रेस), धनंजय मुंडे, अजित पवार और सुनील तटकरे (एनसीपी) शमिल थे।

पीजेन्ट एण्ड वर्कर्स पार्टी (पी.डब्ल्यू.पी.) के महासचिव, जयंत पाटिल, एमएलसी, जो किसान सभा के संघर्षों में सभी तरह से मदद कर रहे थे, और जनता दल (शरद यादव ग्रुप) के राज्य अध्यक्ष, कपिल पाटिल, एमएलसी भी चर्चा के दौरान उपस्थित थे।

किसान सभा के प्रतिनिधिमंडल में डॉ० अशोक ढवले, विधायक जेपी गावित, सीटू के पूर्व राज्य अध्यक्ष व पूर्व विधायक नरसय्या अदम, किसन गुजर, डॉ० अजीत नवाले, सुभाश चौधरी, सावलीराम पवार, सुनील मालुसरे, इरफान षेख, रतन, बुद्धर, बारक्य मंगत, राडका कलांगदा, उमेश देशमुख, सिधप्पा कलशेट्टी, विलास बाबर और डीवाईएफआई के राज्य उपाध्यक्ष इंद्रजीत गावित। उपरोक्त लगभग सभी एआईकेस राज्य पदाधिकारियों, के साथ ए.आई.ए.डब्ल्यू.यू. के राज्य के नेता मनोहर मुले और सीटू के राज्य के नेता विनोद निकोल भी शामिल थे, जो वास्तव में लॉन्ग मार्च में साथ चले।

मौजूदा सरकार के साथ पहले कड़वे अनुभवों के प्रकाश में, किसान सभा ने षुरुआत में स्पष्ट स्थिति ले ली थी कि वह इस लिखित आश्वासन के बिना इस संघर्श को वापस नहीं लेगा। राज्य सरकार के मुख्य सचिव के हस्ताक्षर के साथ, सभी मांगों पर ये लिखित आश्वासन वार्ता के समापन के एक घंटे के भीतर दिए गए थे। राज्य सरकार के तीन मंत्रियों – भाजपा के चंद्रकांत पाटिल और गिरीश महाजन और शिवसेना के एकनाथ शिंदे आजाद मैदान में जीत की रैली में आए और उन्होंने समझौते को पूरा करने का वादा किया। किसान सभा ने भी जोर देकर कहा कि सम्पन्न हुए समझौते को राज्य विधानसभा में मुख्य मंत्री द्वारा सदन के पटल पर रखा जाना चाहिए। तदनुसार, मुख्यमंत्री ने 13 मार्च को विधान सभा में इस समझौते को पेष किया।

ए.आई.के.एस. की माँगे जिन पर सरकार ने ठोस आरूवासन दिए गए हैं, वह हैं वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) का कार्यान्वयन, नदियों को जोड़ने के प्रस्ताव जिनका, नाषिक, पालघर और ठाणे जिलों में जनजातीय जनता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, किसानों को ऋण माफी, लाभकारी मूल्य, मंदिरों की भूमि, चरागाह भूमि , वष्द्धावस्था पेंषन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों में लाखों किसानों को मुआवजा दिया जाऐ, जिनकी गुलाबी बोल्वर्म कीटों, के हमलों और ओलावृष्टि अन्य मुद्दों से कपास की भारी क्षति हुई है। स्वीकार की गई मांगों का विवरण इस वेबसाइट पर कहीं और दिया गया है।

सीपीआई (एम) के महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई (एम) के राज्य सचिव व पूर्व विधायक नरसय्या अदम, पीडब्ल्यूपी के महासचिव जयंत पाटिल एम.एल.सी., ने 12 मार्च की षाम को आजाद मैदान में 50,000 से अधिक किसानों की बढ़ती ऐक्सक्स जीत रैली को संबोधित किया था। जनता दल (षरद यादव ग्रुप) के प्रदेष अध्यक्ष कपिल पाटिल, एमएलसी, ए.आई.के.एस. के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक, अमरा राम, ए.आई.के.एस. के संयुक्त सचिवों के.के. राघेष, सांसद और विजू कृश्णन, प्रसिद्ध पत्रकार पी. साईंनाथ, सीपीआई (एम) केंद्रीय समिति के सदस्य महेंद्र सिंह, एडवा महासचिव मरियम ढवले और इसके उपाध्यक्ष सुधा सुंदररामन, सीटू उपाध्यक्ष डॉ० डी.एल. कराड और इस लॉन्ग मार्च के नेता – ए.आई.के.एस. के अध्यक्ष डॉ० अशोक धवले, ए.आई.के.एस. के पूर्व राज्य अध्यक्ष जेपी गावित, विधायक, ए.आई.के.एस. राज्य अध्यक्ष किसन गुजर और ए.आई.के.एस. के महासचिव डॉ० अजीत नावले आदि ने सम्बोधित किया। और पहले दिन मके समय ए.आई.के.एस., सी.आई.टी.यू., ए.आई.ए.डब्ल्यू.यू., ए.आई.डब्ल्यू.ए., डी.वाई.एफ.आई., एस. एफ.आई. के अन्य नेताओं और सहयोगी राजनीतिक दलों, संगठनों और व्यक्तियों के व्यापक विस्तार द्वारा सम्बोधित किया गया।

सभी किसानों ने 12 मार्च की रात को मुंबई को छोड़ दिया, इस जीत से जबरदस्त आत्मविश्वास पैदा हुआ, साथ ही राज्य की जनता और देश के प्रति समानतापूर्वक आभारी कृतज्ञता के साथ, जिन्होंने इस संघर्श में पूरी तरह से उन्हें समर्थन दिया था। इस लॉन्ग मार्च को बड़े पैमाने पर राश्ट्रव्यापी सार्वजनिक प्रतिक्रिया, किसान सभा के नेतष्त्व में किसानों द्वारा छेड़े गए, बहादुर, शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक संघर्श की एक स्वीकारोक्ति रही। यह इस तथ्य का भी एक प्रतिबिंब था कि राज्यों और केन्द्रों में भाजपा की अगुवाई वाली सरकारों की नवउदारवादी नीतियों के खिलाफ जरूरी तौर पर भूमि अधिकार, ऋण माफी, लाभकारी कीमतों और पेंशन की उनकी माँगें पूरे भारत के किसानों की वास्तविक माँग थी। और इस लॉन्ग मार्च का एक सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह था कि किसानों ने एक वर्ग के रूप में एकजुट संघर्ष किया, जो धर्म, जाति और पंथ के विभाजन के ऊपर रहा था। इसने सांप्रदायिकता और जातिवाद की अंधेरी शक्तियों से लड़ने का मार्ग दिखाया है।

एक लड़ाई जीती गई है, लेकिन युद्ध अभी भी बना हुआ है और इस युद्ध की जीत के बाद, यह पूरे देश में भी अधिक धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ लड़ेगा!

(अषोक ढवले ए.आई.के.एस. के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने ही लॉन्ग मार्च का नेतृत्व किया)

किसान लॉन्ग मार्च के साथ महाराष्ट्र के मजूदरों एकता

ए.आई.के.एस. द्वारा आयोजित ऐतिहासिक किसान लॉन्ग मार्च को पूरे दिल से समर्थन करते हुए, सीटू नासिक जिला कमेटी ने नासिक में बैनरों और होर्डिंग के साथ ठाणे तक सड़क पर एकत्र होने वाले किसानों और का स्वागत किया; सीटू के राश्ट्रीय उपाध्यक्ष और इसके राज्य अध्यक्ष डॉ० डी.एल. कराड ने रैली की शुरुआत में स्वागत किया, जिसमें सीटू के जिलाध्यक्ष सीताराम थाम्बरे उनके साथ रहे, और वे किसान मार्च में मजदूरों की एकता के प्रतीक के तौर पर कुछ दूरी तक साथ चले। किसानों को लांग मार्च के रास्ते पर चेरफुल घाट, घोट, कलामगांव विक्रोली और सायन में सीटू के स्थानीय नेताओं के नेतृत्व में मजदूरों द्वारा बधाई दी गयी; कोल्हापुर के मजदूरों ने सीटू के राज्य नेता अदम नरसैया के माध्यम से 1 लाख रुपये का दान दिया, पूर्व विधायक और ए.आई.आई.ई.ए. की राज्य इकाई ने 21,000 रुपये का दान दिया। आजाद मैदान में समापन रैली को कराड और अदम नरसैया ने संबोधित किया और राज्य सीटू के सभी नेता भी षामिल हुए थे, जिनमें विवेक मोंटेरियो, सईद अहमद, के.आर. रघु, एस.के. राजे, शुभा शमीम, बापू कवर और अन्य शामिल थे। बिरादराना केन्द्रीय ट्रेड यूनियन नेताओं, एच.एम.एस. के राज्य महासचिव संजय वाधवकर, एटक के राजू देसले, ए.आई.आई.ई.ए. के केनी, राज्य सरकार के कर्मचारियों के नेता, टी.यू.जे.ए.सी. के विस्वास उटागी, एन.टी.यू.आई. के मिलिंद रानाडे ने समर्थन दिया।

कामगार-शेतकारी-शेतमजूर एकजुटी के लाल झंडे को उँचा बनाए रखो

विवेक मौन्टेरियो

सीटू और ए.आई.के.एस. दोनों के झंडे में चमकने वाले, मजदूर–किसान एकजुटता का प्रतीक चिन्ह हथौड़ा और हसुंआ ने महाराष्ट्र में एक नया महत्व हासिल कर लिया है, जो कि ए.आई.के.एस. द्वारा 6 से 12 मार्च तक आयोजित छह दिन के ऐतिहासिक किसान लॉन्ग मार्च का परिणाम है।

हाल के वर्षों में किसानों और महाराष्ट्र के आदिवासियों के बढ़ते संघर्षों की पृष्ठभूमि में लॉन्ग मार्च का आयोजन किया गया। 2016 में, ए.आई.के.एस. द्वारा आयोजित एक विशाल दो दिन महापड़ाव और नासिक में सड़क की नाकाबंदी ने महाराष्ट्र सरकार से कई मांगों पर आश्वासन हासिल किया था। मई/जून 2017 में किसानों की संयुक्त कार्रवाई समिति ने छह दिन की एक ऐतिहासिक हड़ताल की। इन प्रत्येक आंदोलनों के समर्थन में नासिक, मुंबई, सोलापुर और अन्य विभिन्न केंद्रों में सीटू ने औद्योगिक मजदूरों द्वारा प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। अक्टूबर 2015 में, सीटू, ए.आई.के.एस. और ए.आई.ए.डब्ल्यू.यू. ने मजदूरों, किसानों और खेत मजदूरों की एक श्रमिक संघर्ष परिषद, का सम्मेलन संयुक्त रूप से परभनी में आयोजित किया; जिसमें नवउदारवादी आर्थिक नीतियों के विरुद्ध लड़ने और वैकल्पिक नीतियों को बड़े पैमाने पर समर्थन देने के लिए मजदूर–किसान एकजुटता को मजबूत करने का संकल्प लिया गया। इसके बाद, जनवरी 2016 में, पूरे राज्य में रास्ता रोको आयोजित किया गया जिसमें औद्योगिक मजूदूरों और किसानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। 2015 और 2016 के 2 सितंबर को सभी ट्रेड यूनियनों द्वारा आहुत हड़तालों के समर्थन में, अखिल भारतीय किसान सभा और अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के कार्यकर्ताओं ने पूरे राज्य में प्रदर्षन और रास्ता रोको का आयोजन किया।
लॉन्ग मार्च के पहले दिन 6 मार्च को, किसान भाइयों और बहनों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए, सीटू महाराष्ट्र राज्य कमेटी के अध्यक्ष डी.एल. कराड और एटक के राजू देसले, ने मजदूर कार्यकर्ताओं के साथ इस मार्च में भाग लिया। जैसे–जैसे यह मार्च नासिक घाटों से उतरकर और वैतरण नदी की तरह मुंबई की तरफ बढ़ता गया, इसकी ताकत में वृद्धि होती गयी। रास्ते में इसमें अकोला, ठाणे और अन्य जिलों की सहायक नदियाँ भी जुड़ती गयीं।

इगतपुरी, शाहपुर, भिवंडी आदि में विभिन्न मध्यस्थ स्थानों पर, कारखानों और पॉवर लूम के सीटू के मजदूरों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया। जब किसानों के इस लॉन्ग मार्च ने, उत्तर–पूर्व उपनगर मुलुंड से मुंबई में प्रवेश किया, सीटू, सीपीआई (एम), डी.वाई. एफ.आई. एडवा, एस.एफ.आई. और अन्य वामपंथी संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाई–वे के कन्ज्यूरमार्ग फ्लाईओवर और रमाबाई नगर, घाटकोपर में एकत्रित हुए थे।
लेकिन, जिसकी योजना भी नहीं बनाई गई थी वह भी देखने को मिला कि मुंबई के नागरिकों, सामाजिक और राजनीतिक संगठनों की भारी प्रतिक्रिया, जो भोजन और पानी की आपूर्ति के साथ सड़कों पर आकर मार्च करने वालों का स्वागत कर रहे थे। यह प्रतिक्रिया इतनी बड़ी और विविध थी कि इसमें शमिल सभी संगठनों को सूचीबद्ध करना भी मुश्किल है। इसमें आवासीय सोसायटी समूहों, युवा मंडलों, सामाजिक सेवा समूहों, दलित संगठनों, सिख, मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध समुदायों से अल्पसंख्यक संगठनों और कई राजनीतिक दलों की भागीदारी रही है। एक बिंदु जो मीडिया टिप्पणी करता रहा है कि केवल भाजपा–आरएसएस के एकमात्र संगठन स्पश्ट रूप से अनुपस्थित थे।

सीटू की ओर से 12 मार्च को आजाद मैदान में अखिल भारतीय किसान सभा की विशाल सभा को संबोधित करते हुए डॉ० डी. एल. कराड ने कहा कि नासिक से मुंबई तक छह दिन का ऐतिहासिक किसान मार्च और मजदूर वर्ग से प्राप्त भारी समर्थन, महाराष्ट्र में मजदूरों और किसानों की एकजुटता की अवधारणा का एक जीवंत उदाहरण है, जो कि कॉमरेड लेनिन द्वारा दुनिया को बदलने और एक नए समाज के निर्माण की बुनियाद के रूप में प्रस्तुत किया गया। यह भाजपा–आरएसएस गुंडों के लिए एक उचित और लड़ाकू प्रतिक्रिया है, जिन्होंने बेलोनिया, त्रिपुरा में लेनिन प्रतिमा को नष्ट कर दिया। मेहनतकशों की इस एकता के आधार पर, यह हम ही हैं जो हमारे देश से जन–विरोधी, सांप्रदायिक और विभाजनकारी राजनीतिक ताकतों को उखाड़कर फेंक देगा। मजदूर–किसान की एकता की इस वर्तमान एकजुटता के महत्व और प्रासंगिकता पर कामगार संघटन संयुक्त कृति समिति (ट्रेड यूनियन संयुक्त एक्षन कमेटी) के अन्य ट्रेड यूनियन नेताओं द्वारा भी जोर दिया जिन्होंने इस बैठक में अपनी बात रखी उनमें सर्व श्रमिक संघ के मिलिंद रानाडे, के.एस.एस.के. के संयुक्त संयोजक विष्वास उटाजी, और एच.एम.एस. के राज्य महासचिव संजय वाधवकर शामिल हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि बेमिसाल अनुशासन और दृढ़ संकल्प के साथ किसान लॉन्ग मार्च ने महाराष्ट्र में वामपंथीं और लोकतांत्रिक विचारधारा के लिए नया समर्थन हासिल किया है जो न केवल गरीब जनता के बीच बल्कि मध्य वर्ग के लोकतांत्रिक हिस्सों में भी मिला है। खेती करने वालों के मुद्दों के लिए सम्मान और सहानुभूति के संदर्भ में, मीडिया के अधिकांश वर्गों को मार्च की प्रगति की रिपोर्ट करने के लिए मजबूर किया। लॉन्ग मार्च ने संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में, संघर्शरत कामकाजी लोगों के सभी वर्गों में विश्वास को उँचा उठाया है। इसने हथौड़ा और हँसुआ के साथ लाल झंडे की प्रतिश्ठा को बढ़ाया है। यह भाजपा–आरएसएसके नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार के छद्म राश्ट्रवादी और जन–विरोधी राजनीति के वास्तविक चेहरे को उजागर करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

उद्योग व क्षेत्र

बिजली

बिजली कर्मचारियों का संसद कूंच

नेशनल कोओर्डीनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रीसिटी एम्पालाईज एण्ड इन्जीनियर्स (एन.सी.सी.ओ.ई.ई.) के आह्वान् पर, देश के विभिन्न हिस्सों से आऐ लगभग 25,000 बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों ने 3 अप्रैल को, कर्मचारी–विरोध और जन–विरोधी बिजली विधेयक 2014 के विरोध में संसद पर कूंच किया और नई दिल्ली के संसद मार्ग पर भारी रैली आयोजित की। इस रैली ने विधेयक के खिलाफ संसद के मानसून सत्र के दौरान कर्मचारियों और जनता की एकता के साथ देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। एन.सी.सी.ओ.ई.ई. के संयोजक प्रशान्त नंदी चौधुरी के द्वारा पेष किए गए एक प्रस्ताव में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और फैडरेशनों के राश्ट्रीय सम्मेलन में बिजली कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल के दिन को घोषित करने का प्रस्ताव रखा।

रैली ने निजीकरण के विरुद्ध उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों के संघर्श को भी समर्थन दिया और संघर्शरत कर्मचारियों पर दमनकारी नीतियां अपनाने के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार को चेतावनी दी।

वक्ताओं ने गरीबों को लक्षित करने वाले विधेयक की निंदा की। रैली ने समान कार्य के लिए समान वेतन और ठेका मजदूरों के नियमितीकरण की माँग की।

सीटू के महासचिव तपन सेन, एटक महासचिव अमरजीत कौर, सीटू के राष्ट्रीय सचिव और ई.ई.एफ.आई. के कार्यकारी अध्यक्ष स्वदेश देवराय और इसके राश्ट्रीय अध्यक्ष के.ओ. हबीब, ए.आई.एफ.ई.ई. के मोहन षर्मा, ए.आई.पी.ई.एफ. के षैलेंद्र दुबे और ए.आई.पी.एफ. , ए.आई.एफ.ओ.पी.डी.ई. और टी.एन.ई.बी.पी.डब्ल्यू.यू. के नेताओं ने संघर्ष कर रहे बिजली कर्मचारियों को सम्बोधित करते हुए बधाईयां दीं।

उ.प्र. में बिजली के निजीकरण के खिलाफ विशाल प्रतिरोध

लखनऊ में शक्ति भवन के समक्ष प्रतिरोध

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्श समिति (इलेक्ट्रीसिटी एम्पलाईज ज्वाईन्ट स्ट्रगल कमेटी), उत्तर प्रदेश के बैनर के तहत; राज्य के सभी बिजली निगमों के मजदूरों और इंजीनियरों ने सामूहिक रुप से दिनभर 'काम बहिष्कार' किया और प्रदर्शनों का आयोजन किया और 27 मार्च को राज्य भर में सभी प्रतिश्ठानों के सामने बैठकें की गयी; और उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा बिजली के निजीकरण के फैसले को उलटने की माँग करते हुए 28 मार्च से 'नियमानुसार काम' शुरु कर दिया। अनपारा, ओबरा, पिपरी, पनकी, हरदुआगंज और परीक्षा आदि उत्पादन के परियोजना मुख्यालयों के समक्ष और पूरे राज्य में वितरण निगमों के जिला कार्यालयों के सामने धरना, प्रदर्शन और जन सभाओं को आयोजन किया गया।

लखनऊ में पावर कॉरपोरेशन के मुख्यालय शक्ति भवन के सामने 5000 से अधिक कर्मचारियों और इंजीनियरों ने विरोध प्रदर्शन किया और बैठक आयोजित की, जिसको संयुक्त समिति और केंद्रीय ट्रेड यूनियन के नेताओं ने संबोधित किया।

राज्यों से

आन्ध्र प्रदेश

आशा मजदूरों का राज्य मार्च

हजारों आशा मजदूरों ने अपनी सीटू यूनियन के नेतृत्व में, न्यूनतम् वेतन, दुर्घटना बीमा कवरेज और लम्बे अरसे से बकायों का तुरन्त भुगतान करने आदि माँगों को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को विजयवाड़ा में, राज्य स्तरीय प्रदर्शन का आयोजन किया, पुलिस की भारी घेरेबन्दी को तोड़ने से पहले विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पर कई घंटे तक धरना दिया और यह जुलूस वाया इलुरु लॉक्स, अलंकार सेन्टर की ओर बढ़ गया जहाँ 5 घंटे के धरने ने यातायात को पूरी तरह से ठप्प कर दिया। आशा मजदूरों की रैली को यूनियन और सीटू के राज्य के नेताओं ने सम्बोधित किया।

अंततः चिकित्सा और स्वास्थ्य के राज्य के अतिरिक्त निदेशक, परिवार कल्याण के संयुक्त कमिश्नर और प्रोग्राम अधिकारी आन्दोलन स्थल पर पहुँचे और मजदूरों को आश्वासन दिया कि उनकी माँगों पर विचार के लिए 10 अप्रेल से पहले संयुक्त बैठक बुलायी जाएगी। इस आश्वासन पर आन्दोलन को वापस लिया गया।

राजस्थान

निश्चित अवधि के रोजगार के खिलाफ विरोध

सीटू जनरल कौंसिल मीटिंग के आह्वान् पर और केरल के हड़ताली मजदूरों के समर्थन में 2 अप्रेल को जयपुर में किसान मजदूर भवन से मजदूरों का एक जुलूस राज्य के श्रम विभाग के कार्यालय गया और निश्चित अवधि के रोजगार के बारे में केन्द्र सरकार की अधिसूचना को वापस लेने की माँग करते हुए प्रदर्शन किया गया। राज्य के श्रम मंत्री को दफ्तर पहुँचने पर प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। निश्चित अवधि का रोजगार, बेरोजगार नौजवानों को स्थायी रोजगार पाने से वंचित करता है और ठेका मजदूरों को उनकी नौकरी के स्थायी होने महरुम करता है। प्रधानमंत्री और केन्द्रीय श्रम मंत्री को माँगों का एक ज्ञापन अतिरिक्त श्रम आयुक्त के माध्यम से पेश किया गया।

मीटिंग को राज्य सीटू के अध्यक्ष रविन्द्र शुक्ला, सचिव भंवर सिंह, जिला अध्यक्ष किशन सिंह राठौर, एटक के राज्य के नेता डी.के. छंगानी और अन्य नेताओं ने सम्बोधित किया।

मजदूरों की रैली ने, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार निरोधक कानून को कमजोर करने वाले सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के विरोध में इसी दिन अनेक दलित संगठनों द्वारा आहुत भारत बन्द का समर्थन किया।

अंतर्राष्ट्रीय

डब्ल्यू.एफ.टी.यू. की प्रेसीडेन्शियल कौंसिल की मीटिंग

इरान के तेहरान में 25–27 फरवरी 2018 को डब्ल्यू.एफ.टी.यू. की प्रेसीडेन्सियल कौंसिल की मीटिंग आयोजित की गयी। प्रेसीडेन्सियल कौंसिल में सभी महाद्वीपों के 42 देशों की ट्रेड यूनियनों का प्रतिधिनित्व करने वाले 48 सदस्य हैं। 50 से अधिक सदस्यों और आमंत्रितों ने मीटिंग में भाग लिया। सीटू के अध्यक्ष और डब्ल्यू.एफ.टी.यू. की प्रेसीडेन्सियल कौंसिल की सदस्य हेमलता और डब्ल्यू. एफ.टी.यू. के उप महासचिव एवं सीटू के राष्ट्रीय सचिव स्वदेश देवरॉय ने इस मीटिंग में सीटू का प्रतिनिधित्व किया।

मीटिंग का आयोजन करने वाले संसद सदस्य और ईरान वर्कर्स हाऊस के महासचिव इलरेझा महजूब ने प्रतिभागियों को स्वागत करते हुए कहा कि तेहरान में प्रेसीडेन्सियल कौंसिल के सदसयों की मौजूदगी हमारे साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलन को मजबूती मिली है। उद्घाटन सत्र की अध्यक्ष मण्डली में सीटू से हेमलता और एटक से अमरजीत कौर सहित एशिया के प्रतिनिधि शामिल थे।

डब्ल्यू.एफ.टी.यू. के महासचिव जॉर्ज मार्विकोस ने दुनिया भर में सभी साम्राज्यवाद विरोधी संघर्शों, विषेश रूप से ईरान, क्यूबा, उत्तरी कोरिया और वेनेजुएला आदि के लिए एकता और समर्थन को व्यक्त किया। उन्होंने सीरिया, यमन पर अमेरिकी हमलों की निंदा और अपनी मातृभूमि के लिए बहादुरी से लड़ने वाली फिलिस्तीनी जनता के साथ समर्थन जाहिर किया। उन्होंने कहा कि डब्ल्यू.एफ. टी.यू. हमेशा, साम्राज्यवादी दबाव और हस्तक्षेप के बिना अपने भविष्य के बारे में स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक ढंग से निर्णय लेने के जन अधिकार का समर्थन किया।

औपचारिक रूप से पिछले साल के दौरान की गतिविधियों की रिपोर्ट रखने और 2018 में कारवाही के लिए प्रस्तावों को पेश करते हुए मार्विकोस ने कहा कि 2017 डब्ल्यू.एफ.टी.यू. के लिए एक कारवाही का समष्द्ध वर्श था, जो इसके प्रभाव के विस्तार को दर्शाता है। वर्श में 180 देषों के 40 प्रतिनिधियों ने डब्ल्यू.एफ.टी.यू. मुख्यालय का दौरा किया। भारत में डब्लूएफटीयू सहयोगियों ने पूरे देश में अलग–अलग अभियानों और संघर्शों में विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 20 करोड़ मजदूरों को लामबन्द किया। उन्होंने यह भी कहा कि हालांकि अनेक एकजुटता कारवाहियाँ हुई हैं, फिर भी, पूरी दुनिया में मजदूरों पर अंतर्राष्ट्रीय वित्त व्यवस्था निर्देशित नवउदारवादी नीतियों के हमलों के मद्देनजर, अंतर्राष्ट्रीयता और एकजुटता अपर्याप्त है। डब्ल्यू.एफ.टी.यू. सहयोगियों को एकजुटता बढ़ाने की अग्रिम पंक्ति में होना चाहिए। उन्होंने मौजूदा आवष्यकताओं को पूरा करने के लिए डब्ल्यू.एफ.टी.यू. को वित्तीय रूप से मजबूत करने की आवष्यकता पर जोर दिया। मार्विकोस ने 2020 में डब्ल्यू.एफ.टी.यू. की 75वीं वर्शगांठ तक सदस्यता को 10 करोड़ तक पहुंचने के लिए कहा। उन्होंने यह भी प्रस्ताव दिया कि वर्श 2018 को 'ट्रेड यूनियन शिक्षा और प्रशिक्षण' का वर्श और डब्ल्यू.एफ.टी.यू. के स्थापना दिवस और एक्शन डे 3 अक्टूबर को 'सभी को सामाजिक सुरक्षा' की माँग पर ध्यान केंद्रित करके मनाया जाए।

महासचिव द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर चर्चा में 37 वक्ताओं ने भाग लिया और भविश्य की कारवाहियों के लिए फार्मूलों और प्रस्तावों का समर्थन किया। सीटू के हेमलता और स्वदेश देव रॉय ने सीटू की तरफ से बात रखी।

बैठक में डब्ल्यू.एफ.टी.यू. के महासचिव जॉर्ज मावरिकोस को मजदूरों की एक बैठक के लिए अमरीका की यात्रा के लिए वीसा देने से इन्कार करने, साम्राज्यवादी धमकियों और हस्तक्षेपों के विरुद्ध, और उत्तर कोरिया, ईरान, अफगानिस्तान, वेनेजुएला, सीरिया और लेबनान के साथ एकजुटता में कई प्रस्तावों को स्वीकार किया गया। बैठक में क्यूबा के साथ एकजुटता और पूर्वी यरूषलेम को राजधानी के रूप में सहित फिलिस्तीन की मातृभूमि की मांग के प्रस्तावों को भी स्वीकारा गया। यह निर्णय लिया गया था कि प्रेसीडेन्सियल कौंसिल की अगली विस्तारित बैठक डब्लू.एफ.टी.यू. मुख्यालय एथेंस में आयोजित की जाएगी।

बैठक का समापन एक विश्वासपूर्ण नोट के साथ हुआ कि आने वाले दिनों में अपने कैडर की वैचारिक चेतना में वृद्धि के साथ डब्लू.एफ.टी.यू. मजबूत होता जाएगा।

vk|kfxd Jfedk d fy, miHkkDrk eY; lpdk vk/kkj o"k 2001=100

u- 112@6@2006&,ulhihvkb

jkT;	dn	fnlEcj 2017	tuojh 2018
vk/k inn'k	x.Vj	281	280
	gnjkckn	251	251
	fo'kk[kkiÝkue	287	285
	okjxy	290	293
vle	MeMek frulf[k;k	261	258
	xokgkVh	251	250
	ycd flYpj	261	262
	efj;kuh tkjgkV	245	241
	jxkikjk rtij	244	241
fcgkj	e?kj&tekyij	301	306
p.Mhx<	p.Mhx<	279	287
NÝkhlx<	fHkykb	313	314
fnYyh	fnYyh	263	267
Xkkvk	xkvk	293	303
Xktjkr	vgenkckn	271	269
	Hkkouxj	268	267
	jktdkV	274	277
	lijr	263	261
	oMknjk	269	268
gfj;k.kk	Qjhnkckn	259	261
	;euk uxj	275	275
fgekpy	fgekpy çn'k	271	270
tEe ,o d'ehj	Jhuxj	283	285
>kj[k.M	ckdkjk	308	310
	fxfjMhg	331	332
	te'kniij	318	319
	>fj;k	327	336
	dkMek	329	331
	jkph gfV;k	296	298
dukVd	cyxke	287	287
	cxykj	305	310
	gcyh /kkjokM	302	299
	ejdjk	302	300
	eilij	297	298
djy	,.kkdlye@vyob	301	301
	e.MkD;ke	331	325
	fDoyku	284	291
e/; çn'k	Hkkiky	293	293
	fNnokMk	261	264
	bnkj	281	288
	tcyij		

jkT;	dn	fnlcj 2017	tuojh 2018
egjk"V	eEcb	293	292
	ukxiij	316	327
	ukfld	295	311
	i.k	279	289
	'kkykiij	298	297
mMhlk	vkxy&rkypj	304	307
	jkmjdyk	310	308
ikfMpfj	ikfMpfj	313	309
ijtkc	verlj	287	296
	tkyU/kj	288	291
	yf/k;kuk	277	278
jktLFkku	vtej	262	267
	HkhyokMk	280	277
	t;ij	271	274
rfeyukM	pUu	268	266
	dk;EcVj	267	267
	dUuj	284	292
	enjkb	284	297
	lye	275	271
	fr#fpjkiYyh	289	287
f=ijk	f=ijk	293	292
mÝkj çn'k	vkxjk	265	263
	xkft;kckn	309	317
	dkuij	285	292
	y[kuÅ	292	298
	okjk.klh	275	285
if'pe cxky	vklulky	283	288
	nkftfyx	309	310
	nxkiij	273	270
	gfYn;k	313	310
	gkoMk	315	317
	tkyikbxMh	271	276
	dkydkrk	278	279
	jkuhxt	269	271
	flyhxMh	257	260
		268	263
vf[ky Hkkjrh; lpdk		286	288

सीटू का मुखपत्र

सीटू मजदूर

ग्राहक बनें

- **व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए** – वार्षिक ग्राहक शुल्क – रू0 100/–
- **एजेंसी** – कम से कम पाँच प्रतियों; 25% छूट कमीशन के रूप में;
- **भुगतान** – चेक द्वारा – ''सीटू मजदूर'' जो कनारा बैंक, डीडीयू मार्ग शाखा, नई दिल्ली–110002 पर देय

  बैंक मनी ट्रांसफर द्वारा – एसबीए/सीन0 0158101019568;
  आइएफसीकोड : सीएनआरबी 0000158;
- **संपर्क:** ई मेल/पत्र की सूचना के साथ
  प्रबंधक, सीटू मजदूर, सीटू केन्द्र, बी टी आर भवन,
  13 ए राऊज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002; ईमेल: citubtr@gmail.com
  फोन: (011) 23221306 फैक्स: (011) 23221284

डब्ल्यू एफ टी यू अध्यक्षीय परिषद की तेहरान बैठक

(रिपोर्ट पृ० 25)

आंध्र प्रदेश की आशा वर्करों का आंदोलन

(रिपोर्ट पृ० 24)

पुलिस का घेरा तोड़ते हुए

मार्च का दृश्य

दिल्ली में बिजली कर्मचारियों की रैली

(रिपोर्ट पृ० 23)

Posted at NDPSO New Delhi- 1 Postal Regd. No. DL(C)-01/1201/18-20 20 RNI No. 34666/79: 6th-7th of every month Licensed to Post without prepayment under License No.U(C)-38/2018-20 (Date of Publication - 5/04/2018)

महाराष्ट्र में किसानों का लाँग मार्च

लाँग मार्च करते किसान

मुंबई के आजाद मैदान में सी पी आइ (एम) महासचिव सीताराम येचुरी

सीटू नेता डी. एल. कराड संबोधित करते हुए

लाँग मार्च के भागीदार

पैरों के छालों का इलाज करते हुए

तपन सेन द्वारा सेंटर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन्स के लिए मुद्रित और प्रकाशित तथा प्रोग्रैसिव प्रिंटर्स, ए–21 झिलमिल इण्डस्ट्रियल एरिया, शाहदरा, दिल्ली–95 से मुद्रित तथा बी टी रणदिवे भवन, 13–ए राउज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002 से प्रकाशित (फोनः 23221288, 23221306; http://www.citucentre.org, CITU email: citu@bol.net.in, citubtr@gmail.com)

सम्पादक : **के हेमलता**

(रिर्पोट पृ० 24)